● वर्ष-4
● अंक-107
रायपुर, गुरुवार
12 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» औद्योगिक विकास का ताना-बाना...

एनआरसी नहीं तो आधार कार्ड नहीं

असम सरकार का बड़ा फैसला

गुवाहाटी। असम सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि जिन लोगों ने अब तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में आवेदन नहीं किया है, उन्हें अब आधार कार्ड नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला आज मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद लिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कदम बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, पिछले दो महीनों में असम पुलिस,त्रिपुरा पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है। बांग्लादेश से हो रही इस घुसपैठ को लेकर असम सरकार चिंतित है और इस रोकने के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा, हमें अपनी व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है, इसलिए आधार कार्ड प्रक्रिया को कड़ा किया गया है। अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार कार्ड आवेदनकर्ताओं की सत्यापन प्रक्रिया का मुख्य जिम्मेदार होगा। हर जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा।

सरमा ने बताया कि आधार आवेदन के बाद यूआईडीएआई इसे राज्य सरकार

के पास सत्यापन के लिए भेजेगा। इसके बाद स्थानीय सर्किल अधिकारी यह जांच करेंगे कि आवेदक या उनके परिवार ने एनआरसी में आवेदन किया था या नहीं। अगर एनआरसी में आवेदन नहीं किया गया होगा, तो आधार कार्ड का आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और इस बारे में रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि एनआरसी में आवेदन किया गया था, तो सर्किल अधिकारी मामले की जांच करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद अगर अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, तो आधार कार्ड जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नया निर्देश केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं और जिन्होंने एनआरसी में आवेदन नहीं किया है। सरमा ने कहा, इस तरीके से हम आधार कार्ड जारी क रने की प्रक्रिया को और कड़ा करेंगे ताकि कोई भी संदिग्ध व्यकित यह पहचान पत्र हासिल न कर सके। असम में 31 अगस्त 2019 को अंतिम एनआरसी सूची जारी की गई थी, जिसमें 19,06,657 आवेदनकर्ताओं को बाहर किया गया था। कुल 3,11,21,004 नामों को शामिल किया गया था, जबकि 3,30,27,661 लोगों ने एनआरसी में आवेदन किया था।

दिल्ली में बांग्लादेशियों पर एक्शन

राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना निर्देश के बाद दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस ने बुधवार को कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश की। पुलिस को कई संदिग्ध भी मिले हैं। इनकी रिपोर्ट तैयार कर जल्द एफआरआरओ (फारनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन आफिस) को साझा की जा रही है।उपराज्यपाल ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से वापस भेजने के निर्देश दिए थे। इसके तहत दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस की कई टीम ने कालिंदी कुंज स्थित ा फुटा रोड पर सत्यापन अभियान चलाया। इसके तहत यहां रहने वाले करीब 15 महिला, पुरुष व बच्चों के पहचान संबंधी दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की गई। इस दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध भी मिले। उन्होंने खुद को आसाम का बताया, लेकिन पहचान संबंधी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पुलिस ने इनके बारे में सारी जानकारी रिकार्ड में लेकर पता कर रही है।

हरदीभाटा ग्राम पंचायत को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के हरदीभाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार-2024 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार - 2024 समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों हरदीभाटा के सरपंच मुनेन कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों में हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं।

15 राज्यों की 45 पंचायतों व संस्थाओं को दिए गए पुस्कार

इस साल ये पुरस्कार कुल 15 राज्यों की 45 पंचायतों व संस्थाओं को दिए गए। इसी के तहत दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 पंचायतों को प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार कुल 9 विषयों के तहत दिया जाता है। , जिनमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत और महिला हितैषी पंचायत शामिल हैं। ग्राम पंचायत हरदीभाटा को सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए पुरस्कार की राशि भी प्रदान की गई।

महाराष्ट्र चुनाव में 1,440 वीवीपैट का किया गया सत्यापन

मुंबई। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण कुलकर्णी ने बताया कि पिछले महीने हुए राज्य विधानसभा चुनावों में 1,440 वीवीपैट (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की जांच की गई और उनके परिणाम ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की गिनती से पूरी तरह मेल खाते पाए गए।

वीवीपैट, ईवीएम से जुड़ा एक उपकरण है जो वोट की पुष्टि के लिए एक पर्ची प्रिंट करता है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मतदाता का वोट सही तरीके से दर्ज हो रहा है। एसीईओ कुलकर्णी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर जोर देते हुए कहा कि ये मशीनें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और इन्हें हैक करना असंभव है। यह बयान विपक्षी दलों की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाने और बैलेट पेपर की वापसी की मांग के बीच आया है।

किरण कुलकर्णी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनिवार्य की गई चेकिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को ईवीएम और वीवीपैट की जांच करने का अधिकार है। इस विधानसभा चुनाव में 288 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,440 वीवीपैट की जांच की गई, और सभी के परिणाम ईवीएम से मेल खाते हैं।

आरोपों पर प्रतिक्रिया

कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर किरण कुलकर्णी ने कहा, %ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले चिप्स एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद बदले नहीं जा सकते। ये मशीनें बाहरी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होतीं, जिससे इन्हें हैक करना असंभव हो जाता है। बीड जिले में कथित बूथ कैप्चरिंग के वीडियो पर उन्होंने कहा कि ये वीडियो या तो मौजूदा चुनावों से संबंधित नहीं थे या महाराष्ट्र के नहीं थे। वहीं बैटरी चार्ज के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ईवीएम की बैटरी मोबाइल बैटरी जैसी नहीं होती। यह लंबी अवधि तक चलने वाली होती है और इसकी क्षमता 5 साल की होती है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग हर विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपैट को यादृच्छिक तरीके से चुनकर उनकी पर्चियों की गिनती करता है और उसे ईवीएम के परिणामों से मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया उम्मीदवारों, एजेंटों और अधिकारियों की उपस्थिति में होती है। एसीईओ किरण कुलकर्णी ने आखिरी में कहा, ईवीएम की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

नित्या को मिला नया जीवन

रायपुर। रामकृष्ण साहू एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं और उनकी पत्नी जांत्री साहू घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। उनकी 8 वर्षीय बेटी नित्या की हंसी-खुशी भरी जिंदगी उस दिन अचानक बदल गई, जब खेलते समय वह गिर गई। परिवार ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। जांच में खुलासा हुआ कि नित्या दुर्लभ और गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) से पीड़ित है। यह बीमारी शरीर की तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को कमजोर कर देती है। नित्या की बीमारी ने पूरे परिवार को गहरे चिंता में डाल दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना भी संचालित की जा रही है, जिससे दुर्ग जिले के ग्राम बोरई की निवासी रामकृष्ण साहू के बिटिया को नया जीवन मिला है।

प्रमुख समाचार

बाहरी ताकतें भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहीः धनखड़

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि कुछ ताकतें भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहीं और इसे खंडित करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयता हमारी पहचान है और हम राष्ट्रवाद से कभी समझौता नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को राजस्थान के जयपुर में सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, %कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर, जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहीं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है।% उन्होंने कहा, %आम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, हमें एकजुट होकर हर राष्ट्र-विरोधी %विमर्श% को बेअसर करना होगा।% देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का, सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत 2047 अब सपना नहीं बल्कि लक्ष्य है।

ट्रेन में सीनियर सिटीजन को किराए में छूट नहीं

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बाद से ही भारतीय रेलवे ने यात्रियों को मिलने वाली कई रियायतों पर रोक लगा दी थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर मिलने वाली छूट भी शामिल है। कोरोना महामारी का दौर खत्म होने के बाद लगातार मांग होती रही है कि वरिष्ठ नागरिकों को टिकट की कीमत पर मिलने वाली छूट दोबारा शुरू की जाए। फिलहाल अब तक कोरोना से पहले वाली स्थिति बहाल नहीं हो पाई है। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे अब कब से छूट देगा इसे लेकर संसद के शीत सत्र में सवाल पूछा गया है। जवाब में रेल मंत्रालय ने कहा कि, फिलहाल देश में दिव्यांगों की चार श्रेणी, मरीजों की 11 श्रेणी और छात्रों की 8 श्रेणी को छूट दी जा रही है। रेलवे मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि, साल 2022-23 में रेल मंत्रालय की तरफ से ट्रेन में सफर करने वाले तमाम यात्रियों पर सब्सिडी के रूप में 56,993 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मंत्रालय ने उदाहरण देते हुए कहा कि, अगर रेलवे एक यात्री को 100 रुपए की सुविधा देता है तो उस यात्री से टिकट की 46 फीसदी कम कीमत यानी सिर्फ 54 रुपये ही वसूलता है।

सदन में टीएमसी सांसद ने सिंधिया पर की विवादित टिप्पणी

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विवादित टिप्पणी की। इसे लेकर भाजपा सांसदों ने सदन में हंगामा किया। इसके चलते सदन की कार्रवाई दो बार कुछ देर के लिए स्थगित की गई। मगर भाजपा सांसदों के हंगामे के बाद कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी सांसद की टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने के निर्देश दिए हैं। उधर, भाजपा की महिला सांसदों ने केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात करके टीएमसी सांसद की शिकायत की। लोकसभा में बुधवार को आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा चल रही थी। इस चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीमएसी) सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की मदद न करने का आरोप लगाया। उनकी बात का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विरोध किया। इसे लेकर दोनों में तीखी नोंक-झोक होने लगी।

केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ 3000 पन्नों के दिए सबूत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने चुनाव आयोग पहुंचे थे। केजरीवाल ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट से वोट काटने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उनके सामने 3000 पन्नों के सबूत सौंपे कि कैसे बीजेपी दिल्ली के लोगों के वोट काटने की साजिश कर रही है। गरीबों, अनुसूचित जाति और दलितों के वोट काटे जा रहे हैं। एक वोट का महत्व आप भली-भांति जानते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने चुनाव आयुक्त को बताया कि कैसे एक बीजेपी सदस्य ने शाहदरा इलाके में 11,000 लोगों के वोट काटने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया को रोका जाए और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए जिन्होंने बड़े पैमाने पर नाम हटाने का आवेदन किया है। श्रष्ट ने कहा है कि चुनाव से पहले कोई भी बड़े पैमाने पर डिलीट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न विधानसभाओं में हज़ारों मतदाताओं के नाम काटने की आवेदन चुनाव आयोग को दी हैं।

भारत की 15 हजार किमी रेलवे ट्रैक पर होगा सुरक्षा

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने एक अत्याधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली कवच का अनावरण किया है जो स्वदेशी तकनीक में एक सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। कवच को ट्रेन संचालन के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा की एक मजबूत परत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रतिष्ठित सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 (एसआईएल-4) से प्रमाणित, कवच इसकी असाधारण विश्वसनीयता का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि 10 हजार लोकोमोटिव और 15 हजार किमी रेलवे ट्रैक पर कवच का काम चालू हो चुका है। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि विकसित देशों ने जो काम 20 साल में किया, उतना काम भारत ने 5 साल में किया है। उन्होंने बताया कि कवच लगने से 10 द्यद्व दूर का सिग्नल ड्राइवर को केबिन में मिल जाएगा। बाहर कुहासा हो, तो भी कवच से सिग्नल मिलेगा। ओवर स्पीड होने पर कवच ऑटोमैटिक ब्रेक लगा देगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ट्रायल के दौरान लोको पायलट के चेहरे पर कितनी खुशी थी। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) एक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि ट्रेन की गति सिग्नलिंग प्रणाली द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर बनी रहे।

इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस पर दबाव बनने लगा, इस दरार का मतलब

नीरजा चौधरी

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद ही, जहां कांग्रेस को मात्र छह सीटें मिली थीं, इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस पर दबाव बनने लगा था। दरअसल वहां मतदान के दौरान ही नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी जताते कहा था कि कांग्रेस से जितनी उम्मीद थी, उसने उतना काम नहीं किया। फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पक्ष में बने माहौल के बावजूद पार्टी के अंदर टिकट वितरण से लेकर मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी को लेकर जिस तरह की कवायद शुरू हुई, उससे उसका बना-बनाया खेल बिगड़ गया।

हरियाणा में कांग्रेस की हार बहुत बड़ा राजनीतिक झटका थी। मानो यही काफी न हो, जिस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन अच्छा था, वहां विधानसभा चुनाव में गठबंधन बुरी तरह बिखर गया। हालांकि झारखंड में इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई, लेकिन वहां भी हेमंत सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा ही मुख्य भूमिका में था। लेकिन दोनों ही जगहों पर- जम्मू-कश्मीर और झारखंड में- कांग्रेस जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही।

इसके बरक्स लोकसभा चुनाव से पहले के माहौल को याद करें, तो राहुल गांधी की दो पदयात्राओं ने उनके पक्ष में हवा बना दी थी। फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं और भाजपा को बहुमत से दूर कर दिया। संसद में वह नेता विपक्ष चुने गये। वैसे में राहुल गांधी को अघोषित तौर पर एकजुट विपक्ष, यानी इंडिया गठबंधन का नेता मान लिया गया था। लेकिन उसके बाद चार राज्यों के विधानसभा चुनावों ने कांग्रेस की स्थिति खराब कर दी। लोकसभा चुनाव और उसके बाद कांग्रेस ताकतवर स्थिति में दिख रही थी, तो विपक्ष में राहुल गांधी के कद को स्वीकारा

जा रहा था। लेकिन चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद कांग्रेस फिर विफलता के पुराने दिनों में लौट आयी है।

इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को आंखें दिखाने की शुरुआत सबसे पहले सपा ने की। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद के संसद सत्र में लोकसभा में विपक्षी नेताओं के बैठने की जो व्यवस्था की गयी थी, उसमें अयोध्या से जीते सपा के सांसद अवधेश प्रसाद को आगे की सीट दी गयी। लेकिन वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनकर आते ही बैठने की व्यवस्था में बदलाव हुआ और अवधेश प्रसाद को पीछे की सीट दी गयी। सपा ने इसे अपना अपमान माना और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना।

सपा के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का मुद्दा पहले कभी इस तरह नहीं उठा। जाहिर है कि ऐसा कहकर वह राहुल गांधी को निशाना बना रही हैं। तृणमूल कांग्रेस वह पार्टी है, जिसका कांग्रेस से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में उसने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने से मना कर दिया था। संसद के मौजूदा शीत सत्र में अदाणी पर हमला बोलने के कांग्रेस के एजेंडे को उसने स्वीकार नहीं किया।

इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी वह कांग्रेस से अलग अपना रास्ता चलती हैं। चूंकि राहुल गांधी अपने सहयोगियों के निशाने पर हैं, ऐसे में, भाजपा भी मौके का फायदा उठाकर यह कहने से नहीं चूक रही कि इंडिया के सहयोगी दलों को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। इस बीच तेजस्वी यादव ने भी यह टिप्पणी की है कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व का मुद्दा सर्वसहमति से तय होना चाहिए। चूंकि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में, तेजस्वी यह कहकर शायद संभावित सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा भले ही किसी कारण से जतायी हो, लेकिन सच यह है कि मौजूदा स्थिति में वह इस गठबंधन का नेतृत्व करने का माद्दा रखती हैं। वह ममता बनर्जी ही हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर दशकों से काबिज वाम मोर्चा को उखाड़ फेंका था। वह ममता बनर्जी ही हैं, जिन्होंने एक से अधिक बार राज्य की सत्ता में भाजपा को आने से रोका है। वह ममता ही हैं, जो पश्चिम बंगाल में भाजपा की आक्रामकता का जवाब उसी आक्रामकता से देती हैं। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, इसका आइडिया भी ममता बनर्जी का ही था।

इंडिया गठबंधन का उद्देश्य भाजपा का कुशलता से मुकाबला करना है। इस मामले में इंडिया गठबंधन के अंदर ममता जैसा रिकॉर्ड दूसरी किसी भी पार्टी का नहीं है। फिर उन्हें इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? चूंकि वह एक महिला हैं, इस कारण भी उन्हें नेतृत्व का अवसर दिये जाने का अच्छा संदेश जायेगा। राजनीति में स्त्री शक्ति का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है।

चुनाव में महिलाएं बढ़-चढ़कर वोट करती हैं। नरेंद्र मोदी की चुनावी जीतों में महिला मतदाताओं का बड़ा योगदान है। झारखंड में झामुमो की जीत में कल्पना सोरेन नायिका की तरह उभरी हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की बड़ी जीत में लड़की बहिन योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सुरक्षाबलों और नक्सलियों की बीच मुठभेड़ एक माओवादी ढेर, दो जवान घायल

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों की बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया है। वहीं आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी के दो जवान घायल हो गए हैं। घटनास्थल से पुलिस ने नक्सलियों के कई सामान बरामद किए हैं। ये मुठभेड़ जिले के थाना गंगालूर क्षेत्र के मुनगा के जंगल में हुई है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 40 नक्सलियों की सूचना पर बुधवार सुबह डीआरजी की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इस दौरान मुनगा के जंगल में पहले से घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया।

जवानों ने मौके से एक पिस्टल, जिंदा आईईडी और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की है। वहीं नक्सलियों ने मुनगा गांव के पास जवानों पर आईईडी ब्लास्ट किया। जिसकी चपेट में आने से डीआरजी के दो जवान

योगेश्वर शोरी व मंगलू कुड़ियाम मामूली रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है यहां उनका इलाज जारी है।

बीजापुर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमनपल्ली गांव में नक्सलियों ने कुड़ियाम माडो (35) की गला घोट कर हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि मंगलवार रात नक्सलियों का दल सोमनल्ली गांव पहुंचा और उन्होंने कुड़ियाम माडो को घर से बाहर निकाला। बाद में नक्सलियों ने माडो की गला घोटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर नक्सली वहां से फरार हो गए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से नक्सलियों के नेशनल पार्क एरिया कमेटी की ओर से जारी पर्चा बरामद किया है जिसमें उन्होंने ग्रामीण पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि फरसेगढ़ थाने की पुलिस ने शव बरामद कर लिया है तथा नक्सलियों की खोज की जा रही है।

खाद्य मंत्री बघेल ने धान खरीदी केंद्र पहुंचकर खरीदी व्यवस्था का लिया जायजा

गुंजेरा में स्टॉक एवं पंजी में अंतर पाए जाने पर नोटिस जारी कर जांच करने के दिए निर्देश

बेमेतरा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल ने मंगलवार को विकासखण्ड नवागढ़ क्षेत्र के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर धान बेचने आए किसानों से चर्चा कर धान खरीदी के संबंध में जानकारी ली। मंत्री श्री बघेल ने धान खरीदी केंद्र झाल, मुरता, संबलपुर, मारो और गुंजेरा का निरीक्षण किया और शासन के मंशानुरूप किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदने के निर्देश दिए।

उन्होंने खरीदी केंद्र गुंजेरा में स्टॉक एवं पंजी में अंतर पाए जाने पर अधिकारियों को नोटिस जारी कर जांच करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री बघेल ने खरीदी केंद्रों में नापतौल, बारदाने की उपलब्धता, खाली बोरा और भरे बोरी को अपने सामने तौलाकर चेक भी किया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि श्री टार्जन साहू, श्री अजय साहू, एसडीएम श्री मुकेश गौड़, तहसीलदार श्री विनोद बंजारे सहित किसान उपस्थित थे।

धान की सही कीमत से किसानों के जीवन में खुशहाली : सुबसो राजवाड़े

कोरिया। छत्तीसगढ़ सरकार की नई धान खरीदी नीति ने किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य देकर एक नई उम्मीद दी है। जूनापारा सरडी की किसान श्रीमती सुबसो राजवाड़े ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें कभी कल्पना भी नहीं थी कि एक दिन प्रदेश में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा।

पति अमर साय राजवाड़े के निधन के बाद खेती-किसानी की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाली श्रीमती सुबसो इस साल 53 क्विंटल धान बेचने धान खरीदी केंद्र पहुंचीं। उन्होंने बताया कि धान खरीदी केंद्र में हमाली और बोरी की व्यवस्था बेहतर है। कर्मचारी सहयोगी हैं, और किसी तरह की पैसे की मांग नहीं की जाती। इससे हमें बिना किसी परेशानी के अपनी फसल बेचने का मौका मिला। धान बिक्री से प्राप्त राशि के बारे में उन्होंने कहा कि इस पैसे का उपयोग खेती के कामों में करूंगी और कुछ राशि बच्चों के भविष्य के लिए जमा करूंगी। उन्होंने इस नीति को किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बताया। श्रीमती सुबसो ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की तारीफ करते हुए कहा, मुख्यमंत्री खुद किसान हैं। यही वजह है कि वे हमारी जरूरतों और समस्याओं को समझते हैं। उनकी नेतृत्व में किसानों को धान की सही कीमत दिलाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उससे किसानों की जिंदगी में सुखद बदलाव आया है। श्रीमती सुबसो ने कहा, किसानों का जीवन खेती-बाड़ी से जुड़ा होता है। सही खरीदी और सही कीमत मिलने से आर्थिक तंगी कम होती है और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है।

शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर पालकों के साथ छात्र निकले पदयात्रा पर

एसडीएम और बीईओ ने तत्काल शिक्षक की व्यवस्था कर भेजा वापस

गरियाबंद। जिले के मैनपुर में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर छात्र आय दिन आंदोलन कर रहे हैं। इधर मुख्यालय के हायर सेकेंडरी का मसला प्रशासन सुलझाने में लगी हुई है। वहीं जिले के गांव भाठापानी में आज शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर प्राइमरी-मिडिल के 25 से अधिक छात्र और उनके पालकों ने मोर्चा खोल दिया। अपनी मांगों को लेकर छात्र अपने पालकों के साथ गांव से जिला मुख्यालय तक पदयात्रा तक ज्ञापन सौंपने निकले थे, जिससे सकते में आकर शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में उनकी शिक्षक की मांग पूरी कर उनकी पदयात्रा को रोका।

जानकारी के मुताबिक, मिडिल स्कूल के शिक्षक को अपने मूल शाला से हटा कर अन्यत्र पदस्थ कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल के भवन भी जर्जर हो गए हैं। स्कूल भवन के लिए मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक भवन नहीं बना है।

पदयात्रा की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, एसडीएम और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने पदयात्रा को बीच में ही रोका और तुरंत एक शिक्षक की व्यवस्था की गई, जिसके बाद छात्रों ने अपनी पदयात्रा समाप्त की। हालांकि स्कूल भवन का मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि स्कूल भवन की मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा।

उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर चैतू नेताम बना सफल कृषक

उत्पादन में बढ़ोत्तरी के साथ आय भी बढ़ी, विष्णु के सुशासन में किसान हो रहे समृद्ध

कोण्डागांव। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू कई है। राज्य के अन्नदाताओं के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा भी दृढ़संकल्पित होकर किसानों के कल्याण और उनके उत्तरोत्तर प्रगति के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जिले के कई किसान भी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर आज समृद्ध एवं खुशहाल किसान के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं।

जिले के विकासखण्ड कोण्डागांव में स्थित ग्राम चिपावण्ड के 67 वर्षीय प्रगतिशील किसान श्री चैतू नेताम ने अपनी मेहनत और नवीनतम कृषि तकनीकों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में सफलता की एक नई मिसाल पेश की है। उनके 03 एकड़ 54 डिसमिल की भूमि पर उन्नत खेती से उन्होंने न केवल अपनी आय में वृद्धि की है, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन गए हैं। पहले चैतू नेताम पारंपरिक तरीके से रागी की खेती करते थे और पुराने ढंग से बीज बोते थे। खरीफ मौसम में पारम्परिक खेती में छिड़कवा विधि से बीज बोने से उत्पादन में ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद कृषि विभाग ने उन्हें आत्मा योजना के तहत नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया, तो उन्होंने रागी की खेती में बदलाव

करने का निर्णय लिया। रबी मौसम में चैतू नेताम ने रागी की फसल की कतार बोनी विधि को अपनाया, जिससे न केवल उनकी फसल का उत्पादन बढ़ा, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि हुई।

चैतू राम ने बताया कि कतार बोनी विधि से बीज का वितरण और सिंचाई ज्यादा व्यवस्थित और नियंत्रित हुआ है, जिसके कारण रागी की फसल का उत्पादन दोगुना हो गया। पहले जहां रागी की खेती 0.405 हेक्टेयर रकबा में उत्पादन केवल 4 क्विंटल होता था और केवल 12 हजार रूपये की आय प्राप्त होती थी। लेकिन अब कृषि में कतार बोनी विधि से बीजोत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से नई तकनीक को अपनाने के बाद उत्पादन 9 क्विंटल हो गया, जिससे 45 हजार रुपये प्राप्त हुआ। इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि के साथ उनके आय में भी वृद्धि हुई।

शासन की योजना से चैतू नेताम के लिए यह बदलाव केवल कृषि के तकनीक में बदलाव नहीं था, बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया। कृषि विभाग से प्राप्त तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उनके लिए काफी लाभदायक साबित हुआ। कतार बोनी विधि से बीजोत्पादन के कार्यक्रम ने उन्हें न केवल अधिक उत्पादन दिया, बल्कि शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय वृद्धि की और खेती के क्षेत्र में तरक्की के राह पर अग्रसर हुए हैं। श्री चैतू राम ने जिले के अन्य किसानों को भी योजना का लाभ लेते हुए प्रशिक्षणक प्राप्त कर कृषि में उन्नत तकनीक अपनाने की अपील की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में राज्य के किसानों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि उनके मेहनत और उत्पादन को उचित दाम भी मिल रहा है। किसानों की मेहनत को शासन की योजनाओं के माध्यम से उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता मिल रहा है, जिससे वे समृद्ध और खुशहाल होने के साथ कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चौतूराम जैसे कई ऐसे किसान हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाते हुए अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं।

युवकों को बेल्ट से बेरहमी से पीटने वाला गुंडा गिरफ्तार

पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस

रायगढ़। रायगढ़ जिले में कुख्यात गुंडा बंटी साहू उर्फ रावण को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रावण सोशल मीडिया पर वायरल दो अलग-अलग मारपीट के वीडियो के बाद से फरार था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की चार टीमें तीन दिनों से लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस साथ ही पुलिस ने आरोपी का शहर में जुलूस भी निकाला। बता दें कि कल मारपीट मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

9 दिसंबर को सोशल मीडिया पर जूटमिल क्षेत्र के बंटी साहू का दो मारपीट वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में बंटी साहू अलग-अलग दो युवकों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा था। इनमें से एक पीड़ित रोमेश साहू ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि बंटी साहू और उसके साथियों ने उसके घर में घुसकर उन्हें बंधक बना कर मारा। इस शिकायत पर जूटमिल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।

पुलिस ने 6 अलग-अलग टीमों का गठन मगलवार को 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सर्द हवाओं ने कराया ठिठुरन का अहसास, अलाव बना सहारा

गौरेला पेंड्रा मरवाही। अमरकंटक की तराई में बसे पेंड्रा गौरेला मरवाही इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दो दिन पहले घने कोहरे से पूरा क्षेत्र कोहरे की चादर में लपटा नजर आने के बाद जब मौसम साफ हुआ तो ठंड का एहसास कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मौसम खुलते ही तापमान नीचे की ओर लुढका और यहां न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रो में ओस की बूंदे भी जमने लगी हैं। दिसंबर के महीने में पेंड्रा गौरेला मरवाही इलाके में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। उत्तर भारत मे हो रही बर्फबारी का असर इस इलाके में भी देखने को मिल रहा है। इलाके का तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां दिन के वक्त धूप न निकलने की वजह से ठंड का एहसास कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठंड की वजह से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग आग से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इलाके में कड़ाके की ठंड शुरू होते ही स्कूली बच्चों की स्कूल टाइमिंग में भी जिला प्रशासन के द्वारा बदलाव कर दिया गया है।

शिक्षक ने सरकारी जमीन पर किया कब्जा

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले मे सरकारी शिक्षक के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे आमापाली गांव के ग्रामीणों ने अपने शिकायत पत्र में कहा है कि उनके गांव के शासकीय भूमि खसरा संख्या 105 लगभग दो एकड़ जिसके अंदर लोकशक्ति तालाब भी है, उस पर जयप्रकाश पटेल उर्फ पन्ना गुरूजी निवासी डूमरपाली तहसील पुसौर ने अवैध कब्जा किया हुआ है। ग्रामीणों का कहना था कि शिक्षक के पैतृक गांव में स्वयं का मकान और कृषिभूमि होनें के बाद भी उनके द्वारा अवैध कब्जा कर अपना व्यावसायिक केंद्र बना लिया गया है। जिसे हटाने हेतु समस्त ग्रामवासी आमापाली एवं ग्राम पंचायत आमापाली के द्वारा प्रस्ताव पारित कर आवेदन पुसौर तहसीलदार को शिकायत किए जाने के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अवैध कब्जे को हटाने की मांग कर रहे हैं।

पीडीएस राशन दुकान में मिल रहा घाटिया चावल

कवर्धा। कबीरधाम के वनांचल में रहने वाले बैगा आदिवासियों को पीडीएस राशन दुकान से खराब चावल बांटने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बाकी की सोसायटी में 735 परिवारों का राशनकार्ड है। हर महीने उन्हें चावल दिया जाता है। लेकिन हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें खराब चावल दिया जाता है। कई बार इसके लिए उन्होंने कहा भी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोसायटी में चावल लेने आए हितग्राहियों ने बताया कि इस तरह के घाटिया चावल का वितरण पहली बार नहीं हो रहा है। हर महीने इसी तरह का चावल दिया जाता है। लेकिन ये चावल लेना मजबूरी बन गई है। हितग्राही प्रभु बैगा ने कहा सोसायटी का चावल साफ करके खाना पड़ता है। कभी शिकायत नहीं किए। हमेशा से ऐसा ही चावल मिलता है। इस सोसयटी से 735 परिवारों का राशन कार्ड है। हर महीने 24 टन चावल आता है। जिसमें कई हाथ की सिलाई वाली बोरिया आती है। इन बोरियों में चावल काफी खराब आता है। उसमें मिट्टी और इल्लियां लगी रहती है। बोड़ला या सिघारी गोदाम से चावल की सप्लाई की जाती है।

खेत में आग लगने से 10 एकड़ की गन्ना फसल बर्बाद

कवर्धा। कबीरधाम जिले में एक बार फिर आग से गन्ना फसल को नुकसान पहुंचा है। घटना सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत गांव सोनपुरी का है। जहां बुधवार सुबह 11 सड़क किनारे लगी गन्ना फसल में आग लग गई। आग की लपटों ने देखते-देखते विकराल रुप ले लिया।ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की।लेकिन आग ने धीरे-धीरे करके 10 एकड़ की गन्ना फसल बर्बाद को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि किसान छैल बिहारी साहू निवासी खडौदा सिंघनपुरी ने सोनपुरी गांव में दूसरे किसान के खेत को लीज पर लेकर खेती की थी। फसल तैयार भी हो चुकी थी।जिसे काटने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान खेत में आग लग गई। जिसके कारण किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि कबीरधाम जिले में लगातार गन्ना और धान फसलों में आगजनी की पिछले 7 दिनों में ये तीसरी घटना है।

विराट वीर मेला में दिखी आदिवासी परंपरा की झलक

बालोद। बालोद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के राजराव पठार में विराट वीर मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर आदिवासी संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिल रही है। यहां पर अंचल से देवी देवता भी पहुंचे हुए हैं। जहां देव जातरा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। दूर-दूर से आंगा देव पहुंचे हुए हैं। यहां पर धमतरी की पायल नेताम ने बताया कि पहनावा और संस्कृति की अनुपम मिसाल यहां देखने को मिल रही है। युवा प्रभाग से अपनी सेवा दे रहे नवीन सलाम ने बताया कि छत्तीसगढ़ के यह सबसे बड़े मेले में से एक है। यहां पर बस्तर से भी लोग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यह विराट वीर मेला का 11वां वर्ष है। यहां पर संस्कृति सभ्यता और एकजुटता की मिसाल देखने को मिल रही है। ये मेला शहीद वीर नारायण की पुण्य तिथि पर मनाया जाता है। आयोजन के दौरान आगा देव अचानक मंच के समीप पहुंच गए। जिसमें देवी देवता सवार थी। इसके बाद भीड़ को हटाया गया। फिर देवी देवता की विधि विधान से पूजा करके विदाई दी गई।

माता रुक्मणी आश्रम के चार बच्चे मेकाज में भर्ती

■ इलाज मिलने से पहले एक बच्ची की मौत

जगदलपुर। बीजापुर जिले के धनोरा में संचालित होने वाले माता रुक्मणी आश्रम के 35 बच्चे 2 दिन पहले एक साथ उल्टी, दस्त व बुखार के चलते अचानक से बीमार पड़ गए। मामले की जानकारी लगते ही इन सभी बच्चों को बीजापुर के जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया था, बच्चों की इसी खराब हालत के चलते एक बच्चे को जगदलपुर रेफर किया गया था, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही बच्ची की रास्ते मे ही मौत गई है। वहीं नौ बच्चों कि हालत ज्यादा ख़राब होने से उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कर इलाज

किया जा रहा हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को बेहतर उपचार के लिए मेकाज भेजा गया है।

डॉक्टरों ने बताया कि फूड पॉयजनिंग से 34 बच्चों को अस्पताल लाया गया था, सुबह एक और बच्ची शिवानी तेलम की तबियत ज्यादा बिगड़ने पर उसे यहां लाया गया था। बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जगदलपुर रेफर किया गया था। किंतु रास्ते मे ही बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉजिनिग की वजह से ही बच्चे बीमार हुए है। बता दें रोज कि तरह माता रुकमणी आश्रम में खाना खाने के बाद बच्चों की तबियत अचानक बिगडनें लगी। एक के बाद एक बच्चे उल्टी दस्त का शिकार होते गए। तत्काल उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। जहां उनका इलाज जारी शुरू किया गया। वहीं बुधवार को मेकाज में असरिता तेलाम 10 वर्ष, अंजली तेलाम 10 वर्ष, कामली हेमला 9 वर्ष, एवनशी लेकाम 7 वर्ष को भर्ती किया गया है।

मोबइल टॉर्च की रोशनी से कराया सुरक्षित प्रसव

कोरबा। कोरबा में जिले के नकिया गांव के उपस्वास्थ्य केन्द्र नकिया की महिला स्वास्थ्य कर्मी ने सुरक्षित प्रसव कराया है। बीमार सिस्टम और लाचार मरीज का यह वाकया जिला और खंड मुख्यालय के दूरस्थ ग्राम पंचायत नकिया का है। उपस्वास्थ्य केन्द्र नकिया से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ी कोरवा बसाहट खम्हन में स्थित है।

बीती रात घने जंगल से प्रसव पीड़ा से कराहती शनियारी बाई अपने पति नवल साय पहाड़ी कोरवा के साथ निजी साधन से उपस्वास्थ्य केन्द्र नकिया आए।जांच करने पर स्पष्ट हो गया कि प्रसव की घड़ी भी आ चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने केस किसी दूसरे केंद्र में भेजने का रिस्क उठाना उचित नहीं समझा। इससे समय बर्बाद होने से जच्चा और बच्चा दोनों की जिंदगी को खतरा हो सकता था। ऐसे में बिजली नहीं

होने की विषम परिस्थिति होते हुए भी यहां ड्यूटी पर मौजूद महिला स्वस्थकर्मी ने बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अपने निजी वाहन की बैटरी निकाली और जैसे तैसे बिजली की जुगत की। बैटरी से कमरे में बल्ब और अपने मोबइल टॉर्च की रोशनी से किसी तरह सुरक्षित प्रसव सम्पादित कराया। नकिया उप स्वास्थ्य केंद्र में शासन-प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को स्वास्थ्यगत समस्याओं से उबारने और छोटी मोटी बीमारियों को समय पर नजदीक के उपस्वास्थ्य केंद्र की सुविधा दी है। उन्हें त्वरित उपचार मिल सके, इसी ध्येय से अस्पताल भवन दिया और स्वास्थ्यकर्मी भी नियुक्त किए हैं, जो विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन भलीभांति कर रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज तक इस उपस्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत संसाधनों का अभाव है। अस्पताल आज भी बिना सुरक्षा बाउंड्री के पड़ा है। पानी और बिजली जैसी मुख्य सुविधा से अछूता है। गांव में आज भी न तो सीएसईबी की परम्परागत बिजली और न ही सौर ऊर्जा की जुगत ही उपलब्ध कराई जा सकी है।

ऐसे में यहां रहने वाला चिकित्सकीय स्टॉफ ही नहीं आम ग्रामीण भी कठिनाइयों में जी रहे हैं। दिन के समय सूरज की रोशनी में अपना दैनिक कार्य तो सम्पादित कर लेते हैं, पर दिन डूबते ही रात के अंधेरे में कई प्रकार की समस्याओं से जूझना तो जैसे इनकी किस्मत बन गई है। स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्थिति तब और भी कठिन हो जाती है जब रात के अंधेरे में कोई प्रसव केस आ जाए या चोटिल मरीज अस्पताल पहुंचता है। ऐसी परिस्थितियों से यहां निवासरत स्टॉफ को आए दिन सामना करना पड़ता है।

इस मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी एस एन केसरी ने बताया कि गांव में शुरू से ही बिजली नहीं है इसके लिए व्यवस्था करने पत्राचार किया गया है जहां डीएफएफ फंड के माध्यम से सौर ऊर्जा लगाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रसव के दौरान बिजली व्यवस्था नहीं होने के कारण टॉर्च और बाइक के बैटरी के माध्यम से लाइट जलाया गया और प्रसव कराया गया जहां सुरक्षित प्रसव हुआ है और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पुण्यतिथि पर उन्हें किया याद

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की 12 दिसम्बर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। साय ने उनकी रचनाओं के आम जीवन पर प्रभाव को याद करते हुए कहा कि मैथिलीशरण गुप्त जी की राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत खड़ी बोली की रचनाओं ने भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी रचनाओं के प्रभाव को देखते हुए उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नये कवियों को काव्यलेखन के लिए प्रेरित किया। गुप्त जी को उनके कालजयी साहित्य के लिए पद्मभूषण सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुप्त जी की रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं जो नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेगी।

अपंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर मिलेगी 1 लाख की सहायता राशि

रायपुर। प्रदेश में विष्णुदेव सरकार के एक साल पूर्ण होने पर निर्माणी श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब ऐसे निर्माणी श्रमिक जो कि पंजीकृत नहीं है लेकिन कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि ऐसे निर्माणी श्रमिक जो कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन किसी कारणवश पंजीयन नहीं हो पाया होता है। इसी बीच कार्यस्थल में मृत्यु होने पर श्रमिक के आश्रितों को किसी तरह की आर्थिक सहायता राशि नहीं मिल पाती थी। श्रमिकों की इन परेशानियों को देखते हुए श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर अब विभाग ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करने जा रही है। अभी तक निर्माणी श्रमिक के सामान्य मृत्यु पर 1 लाख, कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख, कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 2.50 लाख की सहायता राशि मिलती है। अब अपंजीकृत निर्माणी श्रमिक के कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि आश्रितों को दी जाएगी।

23 से 28 दिसंबर तक चलेगा नेशनल हाईवे पर विशेष अभियान

रायपुर। प्रदेश में भारी वाहन चालकों की आंखों की जांच के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नेशनल हाइवे में स्थित टोला प्लाजों पर 23 से 28 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान चश्मा नंबर लगने पर उन्हें सामान्य नंबर का चश्मा मौके पर दिया जाएगा। वहीं गंभीर समस्या होने पर आंबेडकर समेत बड़े अस्पतालों में भर्ती कर उनका इलाज किया जाएगा। हैल्थ डायरेक्टर सह कमिश्नर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कहा कि जांच की रिपोर्ट 31 दिसंबर तक भेजना अनिवार्य होगा। जिन जिलों में टोल प्लाजा है, वहां 5 नेत्र सहायकों की ड्यूटी लगाई जानी है। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक नेत्र परीक्षण किया जाएगा। 6 दिनों तक चलने वाले नेत्र परीक्षण में सभी ड्राइवर कवर हो पाएंगे, संभव नहीं लगता।

जलाशय परियोजना के सर्वे कार्य के लिए 2.56 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। राज्य शासन ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड-शंकरगढ़ की बेलकोना जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए दो करोड़ 56 लाख 14 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से सिंचाई परियोजना के सर्वे कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

15 दिसंबर से शादी की शहनाई पर एक माह का विराम

रायपुर। वर्ष 2024 अब समाप्ती की ओर है और आधे माह बाद याने 15 दिसंबर के बाद शादियों के शहनाई की गूंज एक माह तक सुनाई नहीं देगी। देवउठनी एकादशी से शुरू शादी-विवाह के सीजन पर 14 दिसंबर शाम से 1 महीने तक का विराम लग जाएगा। आगामी 15 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही मलमास शुरू होगा। इस दौरान एक महीने में शादी विवाह के कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। दिसंबर के मध्य में खरमास के साथ ही मांगलिक और शुभ कार्यों पर एक महीने विराम रहेगा। मलमास में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। इस दौरान जगह-जगह कथा सुनाई की जाएगी। इससे पहले दिसंबर में बड़े मांगलिक आयोजनों की धूम रहेगी। इसके बाद जनवरी में मकर संक्रांति के बाद से शादियां प्रारंभ होगी।

साय कैबिनेट ने पुलिस विभाग में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद की ओर से द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से

स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुन: भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NeML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात् आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

साय सरकार के कार्यकाल पर कांग्रेस के सवाल पर अजय चंद्राकर बोले-

छत्तीसगढ़ के विकास को खुली आंखों से नहीं देख पा रहे कांग्रेसी

रायपुर। भाजपा के एक साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। इस पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, श्री डी पिक्कर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन काम हो रहे हैं तो खुली आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जज्बे की जरूरत होती है। वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। ऐसी पार्टी के बारे में क्या बोलना। चंद्राकर ने कहा, इटालियन चश्मा देश के लिए है। छत्तीसगढ़ के विकास को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई है। इस पर चंद्राकर ने कहा, दीपक बैज सड़क पर ही कुछ

कर सकते हैं, सदन में तो उनकी टिकट कट गई है। अपनी टिकट नहीं बचा पाए तो सदन का नाम ही नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने तो उनको सड़क के लायक नहीं छोड़ा है।

बीजापुर में नक्सलियों ने भाजपा नेता की हत्या की है। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा, अभी जो वो हरकतें कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए कर रहे हैं। गृहमंत्री का दौरा प्रस्तावित है तो नक्सली दिखा रहे हैं कि हम एक्टिव हैं। उसके लिए नीचता पूर्व कार्यवाही कर रहे हैं।

मंत्री मंडल विस्तार को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मोदी जी की मंशा है। मंत्री मंडल का विस्तार हो न हो, सरकार अच्छे से चल रही है। हो सकता है इसी नीति पर काम हो। नड्डा के दौरे से पहले भाजपा की बड़ी बैठक को लेकर चंद्राकर ने कहा, रिपोर्ट कार्ड को लेकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जब चाहे तब मंत्रीमंडल का विस्तार कर सकते हैं। एक साल में गिनाने कहने सबके लिए बहुत कुछ है। समाज के उस वर्गों तक संदेश देने की कोशिश होगी, जिनके लिए काम हुए हैं।

कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, क्या बदलाव होगा, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। ताश में 52 पत्ते हैं उसी को फेट रहे हैं। ना जनता जुड़ रही है ना नेता पैदा हो रहे हैं। गांधी परिवार के बाहर से लाएंगे क्या? दीपक बैज सज्जन व्यक्ति है। उन्हें बघेल के छाए से निकलना चाहिए।

कांग्रेस के सवालों पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी का पलटवार, कहा-

पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ को किया कंगाल, हर जगह था माफिया राज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 2023 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का जनादेश दिया। साय सरकार ने एक साल के कार्यकाल में अधिकतर वादे पूरे किए। किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। कांग्रेस ने साय सरकार के एक साल के कार्यकाल पर कई सवाल उठाए हैं। जिस पर वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, सवालों में कांग्रेस का माफिया राज ही नजर आयेगा। 100 नहीं बल्कि 800 सवाल करें, उनका माफियाराज ही सामने आयेगा।

वित्तीय भार को विभाग ने मैनेज करने की रणनीति पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछली सरकार पर निशाना साधा है। मंत्री चौधरी ने कहा, पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ को कंगाल कर दिया था। हर जगह को माफिया राज बना दिया था। पुराने स्कीम, वेतन और सैलरी के वित्तीय बर्डन के साथ सरकार की कई योजनाएं भी चल रही थी। निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन कांग्रेस के लोग कर्जा लेकर अपना जेब भरने का काम करते थे। ऋण से उधार लेकर साय सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर उपयोग करेगी।

मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

के नेतृत्व में एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होने वाला है, इसपर चर्चा होगी। इस एक साल में सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। यह सभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सब हो पाया है।

वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे हो रहे है। इन सभी में इतने सारे उपलब्धि है। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सदन के समक्ष रखेंगे।

रायपुर में स्टार्टअप के लिए युवाओं को सर्वसुविधा युक्त वर्किंग स्पेस

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नव उद्यमियों के लिए एक अच्छी खबर है। रायपुर जिला प्रशासन की ओर से नवनिर्मित को-वर्किंग स्पेस आरंभ से युवाओं को स्टार्टअप में बड़ी मदद मिलेगी। सर्वसुविधा युक्त इस उपयुक्त स्थान में बैठकर युवा अपने बिजनेस को नई ऊंचाईयों में पहुंचा सकेंगे। यहां प्राइवेट केबिन, मिनी आडिटोरियम, वीडियो शूटिंग के लिए भी अलग-अलग स्पेस है। साथ ही हाईस्पीड इंटरनेट की व्यवस्था के साथ कैफेटेरिया की व्यवस्था है।

वर्तमान में कई स्टार्टअप कंपनियां सर्वसुविधा युक्त को-वर्किंग स्पेस में बैठकर अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए है। सोशल सेलर टेक्नोलॉजी कंपनी से जुड़ी अर्पिता हरिहरनो का कहना है कि यह को-वर्किंग स्पेस स्टार्ट के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। यहां पर हर तरह की सुविधाएं एक ऑफिस जैसा उपलब्ध है। मीटिंग के लिए, अलग से केबिन की सुविधा भी है। अच्छे वातावरण के बीच में यह स्थान है और इससे बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिल रही है। इस

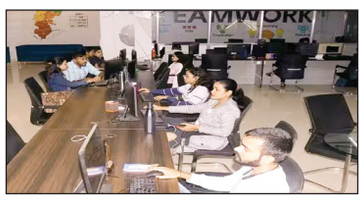

नवाचार के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद देते है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा शहर के बीच में इस तरह की सुविधा देने के लिए आभार जताते है। इस वर्किंग स्पेस में कंपनी के स्टॉफ भी बैठकर बेहतर तरीके से काम-काम कर रहे हैं।

स्टार्टअप शुरू करने वाले सुमीत जैन बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में पहली बार महानगरों की तर्ज पर युवाओं के लिए वर्किंग स्पेस तैयार किया गया है। यहां स्टार्टअप से युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही महानगरों जैसे ऑफिस तैयार किया गया है। वे कहते हैं कि शहर के बीच में ऐसे वर्किंग स्पेस हमारे के लिए बहुत ही फायदेमंद है और शांत वातावरण के बीच में एक बेहतर माहौल में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है।

सीएम ने दो अपेक्स बैंक की शाखाओं का किया वर्चुअल शुभारंभ

चयनित युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सहकारिता विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 334 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले के तमनार और जशपुर जिले के बगीचा में अपेक्स बैंक की दो नवीन शाखा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की नवीन शाखा गढ़पुलझर और सिरपुर का वर्चुअल शुभारंभ और अपेक्स बैंक के नवीन शाखा भवन जशपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया।

सीएम साय ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने प्रवास के दौरान सहकारिता को लेकर अमूल्य सुझाव दिये, जिसे हम कार्यान्वित

कर रहे हैं। सहकारिता का संबंध किसानों से है और हमें साथ मिलकर उनके जीवन में समृद्धि लानी है। उन्होंने सहकारी और अपेक्स बैंक की नई शाखाएं खुलने पर क्षेत्र के किसानों को अपनी शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में सहकारिता की भी बड़ी भूमिका होगी और इसमें आप सभी का योगदान अग्रणी रहेगा। अब प्रदेश के युवाओं के मन में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भय या संशय नहीं होना चाहिए, अब किसान, मजदूर के बेटे-बेटियों की प्रतिभा को सम्मान मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने सभी चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सहकारिता का क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सभी को समझना होगा। किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में आप सभी काम करें। उन्होंने कहा कि बैंक की नई शाखाएं खुलने से किसानों को बड़ी सहूलियत मिलेगी और हम इस दिशा में आगे भी काम करेंगे।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सहकारिता विभाग के फील्ड ऑफिसर कार्यालय सहायक, समिति प्रबंधक समेत 334 पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवार में खुशी का माहौल था। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्रकार सभी चयनित युवाओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि यह हम सभी के जीवन के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। सभी अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की नई पारदर्शी व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

जमीन विवाद को लेकर राजधानी में फायरिंग

रायपुर। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। बुधवार की सुबह जमीन का सीमांकन के दौरान विवाद होने पर आरोपी ने अपने लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, सिविल लाइन थाना अंतर्गत रवि नगर की रहने वाली फजिया मेमन की जमीन रवि नगर रोड पर स्थित है। आज बुधवार को जमीन का सीमांकन होना था। इसी बात को लेकर बुधवार की सुबह फजिया मेमन और हरदयाल के बीच विवाद हुआ। इस बीच फजिया के जमीन में लगा हुआ ताला तोड़कर हरदयाल ने अपना ताला लगा दिया और अपनी जमीन बताने लगा।

पुलिस को पूछताछ में पता चला कि जमीन पर अपने अपने दावे को लेकर विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में हाथापाई की स्थिति भी बन गई। इस बीच फजिया के पक्ष वालों को भगाने के लिए हरदयाल

ने अपने लायसेंसी बंदूक से मौके पर हवाई फायरिंग कर दिया। जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी हरदयाल को गिरफ्तार किया है।

सिविल लाइन थाना प्रभारी रोहित मालेकर ने बताया बुधवार को उस जमीन का सीमांकन होना था। लेकिन सीमांकन के पहले ही फजिया मेमन की जमीन पर बने बाउंड्री वॉल में लगे ताले को हरदयाल ने तोड़कर अपना ताला लगा दिया। महिला को वहां से भगाने के लिए हरदयाल ने अपने लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग करने वाले आरोपी हरदयाल को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी हरदयाल का कहना है कि जमीन दो भाइयों की है। उसके भाई ने अपने जमीन का हिस्सा बेचा होगा, लेकिन उसने अपनी जमीन नहीं बेची है। उसने जमीन के बाउंड्रीवाल के गेट में ताला बंद किया था, जिसे फजिया ने तोड़ दिया था।

दूसरे पक्ष के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हरदयाल को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई कर रही है। आरोपी के पास से दो नली वाली बंदूक और एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान पटवारी और कुछ सरकारी कर्मचारी भी सीमांकन के लिए मौजूद थे। इस मामले में पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है।

डिप्टी सीएम साव के अनुमोदन के बाद 66.06 करोड़ रुपए की पार्षद निधि जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने राज्य के 166 नगरीय निकायों को कुल 66 करोड़ छह लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, 48 नगर पालिकाओं को 20 करोड़ 70 लाख रुपए और 104 नगर पंचायतों को 23 करोड़ 40 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय निकायों के विकास और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये राशि प्रदान की गई है। वार्डों के विकास और आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा।

नगरीय निकायों को जारी की गई पार्षद निधि की यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित कुल निधि का 50 प्रतिशत है। इससे पहले इस वर्ष जुलाई में भी निकायों को 65 करोड़ 72 लाख 24 हजार रुपए का आवंटन जारी किया गया था। पार्षद निधि के रूप में नगर निगमों में प्रत्येक वार्ड के लिए छह लाख रुपए, नगर पालिकाओं में प्रत्येक वार्ड के लिए साढ़े चार लाख रुपए और नगर पंचायतों में प्रत्येक वार्ड के लिए तीन लाख रुपए प्रावधानित है।

डिप्टी सीएम अरुण साव से हाल ही में विभिन्न नगरीय निकायों के पार्षदों ने मुलाकात कर पार्षद निधि की राशि जारी करने की मांग की थी। उनकी मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग को पार्षद निधि जल्द जारी करने के निर्देश दिए थे।

अंतरराष्ट्रीय घेराबंदी और हमारी खामोशी

राजेश बादल

भारत के सिर पर यानी उत्तर में चीन का रवैया छिपा नहीं है। अब उसने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर उत्तर के साथ पूर्व में बांग्लादेश को भारत का कट्टर विरोधी बनाकर करारा झटका दिया है। हमारी सियासी सोच को क्या हो गया है? अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हिन्दुस्तान के लिए दिन-प्रतिदिन जटिल होती जा रही हैं। एक के बाद एक हमारे पड़ोसी राष्ट्र चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं और हम खामोश हैं। हमारी संसद के दोनों सदनों में अभी तक इस बारे में कोई चिंता नहीं दिखाई दी है। (वैसे चिंता तो तब नजर आए,जब दोनों सदनों में कार्रवाई सुचारू रूप से चले। मुल्क की इस सर्वोच्च पंचायत में मोहल्ला या नगरपालिका स्तर के विषयों पर हमारे जन प्रतिनिधि सिर पर संसद उठा लेते हैं लेकिन उन हालातों पर उनकी सोच और जबान पर ताला लग जाता है, जो भारतीय लोकतंत्र को ग्रहण लगाने वाले होते हैं। वे समझते हैं कि देश को अखंड और सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सेना, नौकरशाही और थोड़ी बहुत सरकार की है। संसद के दोनों सदनों के सचिवालय प्रत्येक नए सांसद को सदन के भीतर की कार्यशैली समझाने कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। मगर, हिन्दुस्तान की रक्षा और विदेश नीति के पेंचों को समझाने के लिए आयोजन नहीं होता। जाहिर है इन जन प्रतिनिधियों की ओर से सदनों में वैदेशिक मामलों को उठाने वाले सवाल भी न्यून ही होते हैं। विदेश और रक्षा भी छोड़ दें तो कितने संसद सदस्य ऐसे हैं, जो औद्योगिक परिवेश, कृषि क्षेत्र के बारीक मुद्दे, जंगल से लेकर विज्ञान, शिक्षा और अंतरिक्ष से लेकर आदिवासियों के बारे में अध्ययन करते हैं और सवाल उठाते हैं। इसका उत्तर भी निराशाजनक है। एक संसद की कुर्सी पर 50000 रुपए की गड्डी पर वे तमाशा खड़ा कर सकते हैं। उसे केंद्र में रखकर मुख्य विषय से संसद को भटका सकते हैं, पर गंभीर मामलों पर उनका ध्यान नहीं जाता। घरेलू मसले उन्हें नहीं दिखते। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर वे मुंह नहीं खोलना चाहते। लेकिन भारत के पास पड़ोस का घटनाक्रम भी उन्हें नहीं नजर आता। चाहे वह भारत को दूरगामी दृष्टि से परेशानी में डालने वाला हो। चंद उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करता हूं। भारत के सिर पर यानी उत्तर में चीन का रवैया छिपा नहीं है। अब उसने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर उत्तर के साथ पूर्व में बांग्लादेश को भारत का कट्टर विरोधी बनाकर करारा झटका दिया है। इन दिनों बांग्लादेश को भारत फूटी आंखों नहीं सुहा रहा है। जिसकी कोख से वह निकला और जिसके कारण उसका आज अस्तित्व है, उसी पर हमला करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहा है। यह हमारे राजनयिकों के लिए कोई पहेली नहीं होनी चाहिए कि बांग्लादेश अपने दम पर यह नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से इसके पीछे एक महाशक्ति है। शेख हसीना उसके बारे में खुलासा कर चुकी हैं। इसके बाद अमेरिका के पिछलग्गू ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला किया है। यह निर्णय किंग चार्ल्स ने किया है। उन्होंने भारतीय समुदाय के दो नेताओं को दिए सम्मान वापस ले लिए हैं। इनमें से एक बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बात करने के कारण शिकार बना और दूसरा भारतीय प्रधानमंत्री का समर्थन करने के कारण किंग चार्ल्स का कोप भाजन बना। यह एक ताजी घटना है, लेकिन सीधी बात यह है कि ब्रिटेन भी जो बाइडेन के पीछे खड़ा है, जिन्होंने एक द्वीप अमेरिका को नहीं सौंपने के कारण शेख हसीना की सरकार गिराने का प्रपंच रचा था। अब वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी और जलाई जा रही हैं तथा अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को बिना सुरक्षा जांच के बांग्लादेश में प्रवेश की इजाजत दे दी गई है और भारतीयों की संख्या में कटौती कर दी गई है। कटौती सरकार के सामने शायद अगला संकट यही होगा कि वह बांग्ला भाषा कैसे छोड़े ? यह तो भारतीय भाषा है। लेकिन इस मसले पर हमारी संसद खामोश है। भारत के लोग किस तरह इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह संसद का वह रूप है ,जो किसी बौद्धिक भारतीय को पसंद नहीं आएगा। यह अफसोसजनक है कि भारतीय संविधान के 75 वें वर्ष में संसद का यह सत्र ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें संविधान बनाने वालों की मंशा का आदर नहीं दिखाई देता। क्या अभी भी हमारे जन प्रतिनिधि कोई सबक लेंगे ?

इंडिया गठबंधन में बढ़ती दरारें और मुश्किलें

ललित गर्ग

विपक्षी गठबंधन इंडिया की उलटी गिनती का क्रम रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से आ रही खबरों से साफ होता है कि इंडिया गठबंधन इंडिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा। लगातार चुनावी नाकामियों से पैदा हुई बेचैनी गठजोड़ पर भारी पड़ रही है। एक-दूसरे के खिलाफ असंतोष, दोषारोपण और बयानबाजी विपक्ष एकता के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं, जो गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने का ही सबब है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रभावी प्रदर्शन एवं परिणामों के कारण ही वह अधिकारपूर्वक इंडिया का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर गठबंधन की अगुआई करने में सक्षम हो पायी। लेकिन कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई मजबूत एवं प्रभावी पहल बाद में हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखण्ड, जम्मू-कश्मीर आदि प्रांतों के चुनावों में देखने को नहीं मिली, राज्यों के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी पार्टियों ने अपनी क्षेत्रीय जरूरत को सर्वोपरि रखते हुए फैसले लिए जो गठबंधन की प्रतिबद्धताओं पर प्रश्न लगाती है। अडाणी मुद्दे को लेकर शीतकालीन संसद सत्र में इंडिया गठबंधन में दरार दिखने लगी है। अडानी के मुद्दें पर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार संसद में हंगामा कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई है। वहीं, अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी और टीएमसी कांग्रेस से अलग अपना रुख दिखाते हुए आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं। वैसे भी ये दोनों दल ही 66 सांसदों के साथ गठबंधन के मजबूत आधार है।

निश्चित रूप से कांग्रेस के मुद्दों से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। भाजपा जब कांग्रेस से मुकाबले में होती है तब उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है। जबकि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले राहुल का जादू फीका पड़ता है। इसके उदाहरण हैं झारखंड के हेमंत सोरेन का शानदार प्रदर्शन और बंगाल की ममता बनर्जी जिन्होंने उपचुनाव में सारी सीटें जीत ली। हरियाणा विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद से कांग्रेस के जीत के सपनों को सेंध लगी थी और वहां भाजपा ने शानदार जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने में कामयाब रही। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। आप ने तो कांग्रेस से दूरी बनायी ही है, अन्य दल भी दूरियां बना रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस एवं आप के बीच सहमति नहीं पायी है। आप ने समझ लिया है कि गठबंधन से कांग्रेस को ही फायदा अधिक होता है। इस तरह गठबंधन के टूटन से भाजपा की निराशा के बादल कुछ सीमा तक पहले भी छंटते हुए दिखाई दिये हैं और दिल्ली में ही ऐसा होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस, आप एवं भाजपा के त्रिकोणीय संघर्ष का फायदा भाजपा को ही मिला है और आगे भी ऐसा ही होने की संभावनाएं है।

महाराष्ट्र चुनाव में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया बिखरा हुआ ही प्रतीत हुआ, सपा ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से नाराजगी की बात कहते हुए महाविकास अघाड़ी गुट से नाता तोड़ा, भले इससे राज्य की सियासत पर असर न पड़ा हो, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। इसी तरह, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का इंडिया को लीड करने की इच्छा जाहिर करना भी बहुत कुछ कहता है। इन दोनों की नाराजगी गठबंधन के नेतृत्व और इस तरह से सीधे कांग्रेस को लेकर है। विभिन्न राज्यों में जहां-जहां इंडिया गठबंधन दलों की सरकारें हैं, वे अडाणी जैसे मुद्दों से दूरी बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह यह कहा कि उनका दल कांग्रेस की ओर से उठाए गए किसी एक मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देगा, उससे यही संकेत मिला कि वह नहीं चाहतीं कि अदाणी मामले को तूल दिया जाए। कांग्रेस को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि गत दिवस ही माकपा के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने बंदरगाह के विकास के लिए अदाणी समूह के साथ एक पूरक समझौते को अंतिम रूप दिया। साफ है कि माकपा भी अदाणी मामले में कांग्रेस के रुख से सहमत नहीं। तेलंगाना सरकार ने अदाणी समूह के साथ एक समझौता कर रखा है और अतीत में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी राज्य में इस समूह के निवेश को हरी झंडी दी थी। आखिर राहुल गांधी इन स्थितियों को क्यों नहीं समझ एवं देख रहे हैं?

विपक्ष गठबंधन इंडिया में सबसे ज्यादा कमी आम सहमति की दिखाई देती है। सीटों से लेकर मुद्दों तक, सहयोगी दलों के बीच कहीं एकजुटता एवं आम सहमति नहीं दिखती। इसी शीतकालीन सत्र में अदाणी मामले पर कांग्रेस और टीएमसी ने अलग राह पकड़ ली। दरअसल, यह टकराव राष्ट्रीय राजनीति में फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रही कांग्रेस और अपनी खोयी राजनीतिक जमीन को पाने के लिए लड़ रहीं क्षेत्रीय राजनीति की धुरंधर पार्टियों के बीच का ज्यादा है। देखा जाए तो समय-समय पर इस तरह की खबरें आती रही हैं, जो विपक्षी एकता के लिए चुनौती खड़ी कर देती हैं। कुछ अरसा पहले ही यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच जैसी असहज स्थिति बनी थी, वैसा सहयोगियों के बीच तो नहीं होता। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी सहयोगी दलों में तालमेल की कमी होने की बात सामने आई थी। बंगाल में पहले ही कांग्रेस और टीएमसी एक-दूसरे के विरुद्ध हैं। इसी तरह, दिल्ली में आप और कांग्रेस में गठजोड़ नहीं है। यह कैसा गठबंधन है, जिसमें इतने अंतर्विरोध एवं असहमतियां हों। जहां पार्टियां आम चुनाव में साथ हों, लेकिन राज्यों के चुनाव में आमने-सामने। ऐसे में इन दलों के समर्थकों की उलझन की सहज की कल्पना की जा सकती है और इससे गठबंधन की मूल विचारधारा पर प्रश्न खड़े होने भी स्वाभाविक है। गठबंधन की सफलता के लिये नीति एवं नियत में एकजुटता जरूरी है। गठबंधन तभी सफलता से चलता है, जब सारे पक्ष थोड़ा-थोड़ा त्याग करें और किसी बड़े लक्ष्य को सामने रखे। क्षेत्रीय पार्टियों की बहुलता और अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग क्षेत्रीय पार्टियों की प्रधानता के चलते भी इस तरह के गठबंधन को लंबे समय तक चला पाना मुश्किल हो जाता है। चुनावी हार और सत्ता से बाहर होने की स्थिति में तो ऐसे गठबंधन को संभालना लगभग असंभव ही हो जाता है। ऐसी स्थितियों में क्या इंडिया गठबंधन के भविष्य पर धुंधलके छाने लगे है। क्या वह अंतिम सांसें गिन रहा है। विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि आम चुनाव के बाद वह जितना एकजुट और मजबूत नजर आ रहा था, अब उतना ही बिखरा एवं अलग-थलग होता हुआ दिख रहा है। जम्मू-कश्मीर और झारखंड की जीत इतनी बड़ी नहीं है, जो बाकी हार को छुपा सके। इन दोनों राज्यों में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत में क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका रही और कांग्रेस की कम। इसलिए अब विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी उसे चुनौतियां मिल रही हैं। आने वाले चुनाव विपक्षी गठबंधन के भविष्य के लिए भी अहम और निर्णायक होंगे। विपक्ष की मजबूती उसके खुद के लिए ही नहीं, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। इंडिया गठबंधन का मूल उद्देश्य भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कमजोर करना है, लेकिन इसके लिये कांग्रेस एवं गठबंधन प्रभावी मुद्दें प्रस्तुत करने में नाकाम रही है। जबकि भाजपा ने महाराष्ट्र में हिंदू मतदाताओं के रुझान का ख्याल रखा। इसी के हिसाब से नारे गढ़े। लाडकी बहिन जैसी लाभार्थी योजना, आरक्षण के सवालों और महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दों के इर्द-गिर्द अपनी रणनीति बनाई। लेकिन राहुल गांधी ऐसे चुनावी मुद्दों को गढ़ने में क्यों असफल रहे? इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता राहुल गांधी की इन स्थितियों पर गंभीर मंथन कर रहे हैं। राहुल गांधी बेतुकी आक्रामकता से उपरत क्यों नहीं हो रहे हैं? वे सदन के भीतर एवं सदन के बाहर ऐसी ही तर्कहीन बातों एवं बयानों से अराजक माहौल बना रहे हैं। जिससे कांग्रेस तो कमजोर हो ही रही है, इंडिया गठबंधन भी कमजोर होता जा रहा है, यही बड़ा कारण है इसके बिखराव का, टूटन का।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

गतांक से आगे...

प्रतिवादी को एक बात और भी स्मरण रखनी चाहिये कि स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास के आरम्भ में ही पृष्ठ 264 पर लिखा है कि- महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ और महाभारत के युद्धपर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनो।

चीन का भगदत्त अमेरिका का बज्र वाहन यूरोप देश का विडालाक्ष अर्थात् मार्जार के सदृश आँख वाले, यवन जिसको यूनान कह आए हैं और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूययज्ञ और महा- भारत युद्ध में आज्ञानुसार आये थे।

जब राजसूय यज्ञ में अमेरिका का राजा सम्मिलित हुआ था तो क्या उसने व्यास जी के दर्शन करके अपने देश के हालात नहीं बताए होंगे ? सम्भव है वह स्वयं भी तमाखू पीता हो ! व्यास जी ने इसे बुरी इल्लत समझ कर पुराण बनाते समय उसकी निन्दा की हो। फिर आप तो अमेरिका की राजकन्या से अर्जुन का विवाह मानते हैं, तब तो अर्जुन की बरात में स्वयं व्यास जी ही अमेरिका गये हों या और बारा- तियों ने अमेरिका से लौट कर वहाँ के धूम्रपान का जिक्र किया हो यह बहुत सुसम्भव है।

इस प्रकार प्रत्येक दृष्टिकोण से व्यास जी का तमाखू खण्डन करना युक्तियुक्त ठहर सकता है। इतने पर भी यदि प्रतिवादी अपने आक्षेप के हेत्वाभास को सम्मानपूर्वक वापिस न लेना चाहेगा तो उसे दयानन्दी वेदों को भी कल के बने मानना पड़ेगा, क्योंकि महाशय जी के तर्क को नीचे लिखे शब्दों में भी बदला जा सकता है यथा, तारबर्की नामक किताव में लिखा है कि टेलीग्राफी का आविष्कार भि0 एडीसन साहिब ने विक्टोरिया के जमाने में किया है और दया- नन्द के भाष्यानुसार छेदों में तार विद्या का उल्लेख विद्यमान है।

क्रमशः ...

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

गौरव अवस्थी

करते तुलसीदास जी कैसे मानस-नाद,
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कही गई यह लोकप्रिय पंक्तियां आज भी गुरु-शिष्य परंपरा के लिए कीर्ति स्तंभ हैं। हमारे उन्हीं राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की 12 दिसंबर को 60वीं पुण्यतिथि है। 12 दिसंबर 1964 को उन्होंने अंतिम सांस ली। 3 अगस्त 1886 को चिरगांव (झांसी) में राम भक्त राम चरण एवं काशीबाई के घर जन्मे मैथिलीशरण गुप्त, द्विवेदी युग की देन हैं। खड़ी बोली कविता के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले गुप्त जी ने छह दशक की काव्य साधना में करीब 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की। अतीत वर्तमान और भविष्यत पर आधारित भारत भारती और

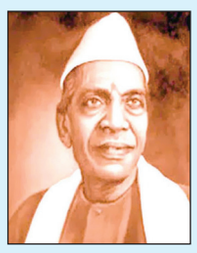

रामचरितमानस की प्रमुख पात्र उर्मिला के चरित्र पर आधारित साकेत उनके महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं।

प्रारंभ में रसिकेंद्र उपनाम से बृजभाषा में कविताएं लिखने वाले मैथिलीशरण गुप्त की अपने समय की प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका सरस्वती में कविताएं छपने की ललक ने उन्हें आमजन की भाषा में आमजन के लिए कविताएं लिखने की तरफ मोड़ दिया। इसका किस्सा यूं है- गुप्तजी ने अपनी बृजभाषा की कविता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास भेजी। उसमें अपना उपनाम रसिकेंद्र भी लिखा। आचार्य जी ने एक पत्र के साथ कविता वापस लौटा दी। पत्र में लिखा-हम सरस्वती में बृजभाषा में कविताएं नहीं छापते। आम जन की भाषा खड़ी बोली में कविताएं लिखिए। और हां! अब रसिकेंद्र बनने का जमाना गया।

आचार्य जी की ऐसी टिप्पणी के बाद गुप्तजी ने बृजभाषा से मुंह मोड़ लिया। रसिकेंद्र उपनाम से तौबा कर ली और खड़ी बोली में कविता लिखनी शुरू कर दीं। सरस्वती में उनकी खड़ी बोली की पहली कविता हेमंत 1905 में प्रकाशित हुई। अगर वह अपनी इस कविता के संबंध में सार्वजनिक रूप से यह न स्वीकारते- मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठा।... पढ़ने पर मेरा आनंद आश्चर्य में बदल गया। इसमें तो इतना संशोधन और परिवर्धन हुआ था कि यह मेरी रचना ही नहीं कही जा सकती थी। कहां वह कंकाल और कहां यह मूर्ति। वह कितना विकृत और यह कितनी परिष्कृत। फिर भी शिल्पी के स्थान पर नाम तो मेरा ही छपा है। मुझे अपनी हीनता पर लज्जा आई और पंडित जी की उदारता देख कर श्रद्धा से मेरा मस्तक झुक गया। तो हिंदी जगत को आचार्य द्विवेदी के श्रमसाध्य संपादन की अनुभूति समय रहते समझने में मुश्किल होती।

हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिलीशरण गुप्त के बीच परस्पर स्नेह और सम्मान के रिश्ते जगजाहिर हैं। आचार्य द्विवेदी न घोषित गुरु थे न राष्ट्रकवि घोषित शिष्य लेकिन दोनों के बीच आपसी समझ गुरु-शिष्य के रिश्ते से बड़ी थी। पवित्र और शीतल थी। दोनों ही एक-दूसरे के पूरक रहे। साहित्य में इसके कई प्रसंग समय-समय पर सामने आते रहे हैं। खड़ी बोली आंदोलन से निकले मैथिलीशरण गुप्त आचार्य द्विवेदी के एकमात्र ऐसे शिष्य है जो परलोक में भी उनके जैसे पथ प्रदर्शक की चाह रखते हैं।

सोरोस के सहयोग से देश को अस्थिर कर रही कांग्रेस?

अभिनय आकाश

देश की संसद में पक्ष और विपक्ष दो उद्योगपतियों के नाम पर बंट गए हैं। एक स्वदेशी बिजनेमैन गौतम अडानी हैं तो दूसरे परदेसी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस हैं। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार से गौतम अडानी की सांठगांठ चल रही है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जार्ज सोरोस के सहयोग से कांग्रेस पार्टी देश को अस्थिर करने का काम कर रही हैं। दोनों धड़ों के पास अपने अपने हिस्से का कागज हैं। वो वो इन कागजों में अपने हिस्से के इल्जाम ढूंढ़ रहे हैं। वहीं समय खराब तो देश की संसद का हो रहा है जो स्थगन की वजह से ज्यादा चर्चा में है। स्थगन से अगर समय बच गया तो सदन चलती है सवाल जवाब होते हैं। देश को अपने जन प्रतिनिधियों का रवैया भी देखने को मिलता है। आज हमने सोचा की क्यों न आपको बताया जाए कि देश की संसद में जिस जॉर्ज सोरोस का नाम उछला वो कौन है? कुछ के लिए इतिहासपुरूष, फाइनेंसियल गुरु और एक सफल निवेशक, एक अरबपति जो बाजारों को स्थानांतरित करने में सक्षम हैं। या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसका सपना भारत और सनातन सभ्यता को नष्ट करना। भारत ही नहीं जार्ज सोरोस का शौक हर उस देश को तबाह करना है जहां पर मानवता के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा हो। किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के बीच सांठगांठ के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का इसके जवाब में क्या कहना है?

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोनिया गांधी और हंगरी-अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बीच संबंध का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर अपना हमला तेज कर दिया है। भगवा पार्टी द्वारा पूर्व कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये कथित संबंध एक गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा

कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं इस पर राजनीति किए बिना उठाना चाहता हूं। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरेस के बीच संबंध गंभीर हैं। हम इसे राजनीतिक रंग देकर नहीं देखना चाहते।

भाजपा ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित संगठन फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स-एशिया पैसिफिक (एफडीएल-एपी) फाउंडेशन से है, जिसने कश्मीर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विचार का समर्थन किया है। सत्तारूढ़ पार्टी ने 'एक्स' पर किए कई सारे पोस्ट में कहा कि यह संबंध भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी संस्थाओं के प्रभाव को दर्शाता है। त्रिवेदी ने दावा किया कि सोनिया गांधी एफडीएल-एपी फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष हैं। एफडीएल-एपी जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित है। विनम्रतापूर्वक, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने एफडीएल-एपी के सह-अध्यक्ष का पद क्यों स्वीकार किया। कांग्रेस-सोरोस की दोस्ती क्या कहलाती है? भाजपा ने आगे आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता के कारण जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुई, जो भारतीय संगठनों पर विदेशी फंडिंग के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। बीजेपी ने कहा कि अडानी समूह पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सम्मेलन का सोरोस द्वारा वित्त पोषित ओसीसीआरपी (संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना) द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया गया था। ओसीसीआरपी एक खोजी पत्रकारिता मंच है जो संगठित अपराध और भ्रष्टाचार की कहानियों पर केंद्रित है। एक अन्य ट्वीट में, भाजपा ने बताया कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कथित तौर पर जॉर्ज सोरोस को पुराने दोस्त के रूप में स्वीकार किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने के लिए भारत को नष्ट करना चाहते हैं, तो वे असफल होंगे। भारत-विरोधी ताकतों और उनके सहयोगियों को भारत हरा देगा। कांग्रेस के सदस्य देशद्रोही ताकतों के साथ अधिकारी बनकर बैठे हैं। भाजपा जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों के साथ कांग्रेस के संबंधों की प्रकृति पर सवाल उठा रही है, जिन्होंने खुलेआम भारत में अस्थिरता पैदा करने और मोदी सरकार को हटाने की इच्छा व्यक्त की है। यह निराशाजनक है कि कांग्रेस देश के बारे में विदेशों से उठ रहे रहस्यमय सवालों का समर्थन करती नजर आ रही है। उनका समर्थन करना देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने जैसा है। कांग्रेस का विदेशी ताकतों के साथ गठबंधन करने का इतिहास रहा है। यह वही कांग्रेस है जिसने तेल कूपन स्वीकार किए और सद्दाम हुसैन से धन प्राप्त किया, जैसा कि 2005 की वोल्कर रिपोर्ट में खुलासा हुआ था।

विपक्षी दलों ने सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी की आलोचना की है। आरोपों को खारिज करते हुए, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इसे कपोर कल्पनाएं करार देते हुए कहा कि इन सब को डार्क वेब तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि इन गहन राज्य सिद्धांतों को डार्क वेब तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, न कि गंभीर राजनीतिक प्रवचन तक। लोगों के पास अंधकारमय, रुग्ण कल्पनाएँ हैं और वे उन्हें जारी रख सकते हैं, और इन सभी षड्यंत्र सिद्धांतों को कोई विश्वसनीयता नहीं दी जाएगी। हम हमेशा भारत की संप्रभुता और एकता के पक्ष में हैं। हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रवादी हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो भारत की अखंडता के खिलाफ हो। राजद सांसद मनोज झा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार और उसके शीर्ष नेतृत्व ने साजिश के सिद्धांतों पर गौर करना शुरू किया, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसे वे छिपाना चाहते हैं। आप सरकार में हैं, चीजों की जांच कराएं।

सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा के आरोप अमेरिकी विदेश विभाग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आए हैं। ओसीसीआरपी का 50 प्रतिशत वित्तपोषण सीधे अमेरिकी विदेश विभाग से आता है। एक पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि ओसीसीआरपी ने डीप स्टेट एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए एक मीडिया टूल के रूप में काम किया है। अमेरिका ने बीजेपी के आरोपों को निराशाजनक बताया है। अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सरकार दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता की चैंपियन रही है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि यह निराशाजनक है कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगाएगी। अमेरिकी सरकार प्रोग्रामिंग पर स्वतंत्र संगठनों के साथ काम करती है जो पत्रकारों के लिए पेशेवर विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का समर्थन करती है। यह प्रोग्रामिंग इन संगठनों के संपादकीय निर्णयों या दिशा को प्रभावित नहीं करती है। अमेरिकी दूतावास के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सोमवार को मैंने अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों का बयान बार-बार पढ़ा. उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिकी सरकार ओसीसीआरपी को फंड देती है और सोरोस का फाउंडेशन भी इसे फंड करता है। उन्होंने हिंदी में एक ट्वीट में आरोप लगाया कि ओसीसीआरपी और सोरोस का काम भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना और विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर मोदी सरकार को बदनाम करना है।

आज का इतिहास

1914 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फिर से खोला गया।
1915 चीन के राष्ट्रपति युवान शी की ने राजतंत्र को पुन: बहाल कर स्वयं को चीन का सम्राट घोषित किया।
1917 फ्रेंच आल्प्स में फ्रांसीसी सेना की ट्रेन के पटरी से उतरने से 543 लोगों की मौत हो गयी।
1917 फ्रांस के मोडेन में ट्रेन के पटरी से उतरने से 500 सैनिकों की मौत हो गई है।
1923 इटली में पो नदी बांध फटने से 600 लोगों मारे गए।
1925 चिली ने राष्ट्रीय पक्षी उदयान का उद्घाटन किया।
1935 नाजी लेबेंसबोर्न कार्यक्रम, जिसे बाद में गलत तरीके से प्रजनन में संलग्न होने के लिए गलत किया गया था, एसएस सदस्यों और अविवाहित माताओं की पत्नियों के लिए भविष्यवाणियां करने के लिए स्थापित किया गया था।
1935 नाजी लेबेन्स का जन्म कार्यक्रम, जिसे बाद में गलती से ज़बरदस्त प्रजनन में संलग्न माना गया था, को एसएस सदस्यों और अविवाहित माताओं की पत्नियों के लिए अनंतिम रूप से स्थापित किया गया था।
1937 जापान द्वारा चीनी जल में अमेरिकी गनबोट पनय के डूबने के लिए जापान माफी मांगता है जो जापान के युद्ध के दौरान जापान के विमान द्वारा चीन के खिलाफ आक्रमण के कारण हुआ था।
1939 रॉयल नेवी विध्वंसक एचएमएस डचेस की घबराहट एचएमएस बरहम द्वारा अभिभूत थी, वह एस्कॉर्टिंग कर रही थी और जीवन की भारी हानि के साथ डूब गई थी।
1942 द्वितीय विश्व युद्ध-जर्मन सैनिकों ने ऑपरेशन विंटर स्ट्रॉम शुरू किया, युद्ध के दौरान एक्सिस सेनाओं को राहत देने के लिए युद्ध की तैयारी की।
1959 उनकपूओस बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों पर संयुक्त राष्ट्र समिति की स्थापना की गई।
1975 चार इरा बंदूकधारियों को दो बंधकों को मुक्त कराने और आत्मसमर्पण करने के बाद लंदन में बालकोम्ब स्ट्रीट में छह दिन का प्रतिबंध शांतिपूर्वक समाप्त हो गया।
1980 अमेरिका ने कॉपीराइट कानून में बदलाव कर उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को शामिल किया।
1985 अमेरिकी एयरफोर्स के 101 वें एयरबोर्न डिवीजन के 248 सदस्यों सहित 256 की हत्या, गांदर, न्यू पाया भूमि और लैब्राडोर में उड़ान भरने के बाद एरो एयर फ्लाइट 1285 दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

सम्राट चौधरी के सियासी उभार से हाशिए पर तेजस्वी यादव?

कमलेश पांडे

बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लुढ़कते जनाधार से सेक्यूलर सियासतदान परेशान हैं। उनकी चिंता है कि भाजपा ने बिहार के युवा नेता और मौजूदा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर दांव क्या लगाया, तेजस्वी यादव जितनी तेजी से उभरे थे, उससे भी तेज गति से हाशिए पर जाते प्रतीत हो रहे हैं! कोई इसे कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भाकपा माले की सियासी शोहबत का साइड इफेक्ट्स करार दे रहा है तो कोई इसे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं से जारी सियासी लुकाछिपी का असर करार दे रहा है।

जबकि राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि लालू प्रसाद की तरह ही तेजस्वी यादव की मुस्लिम परस्त वाली राजनीतिक छवि एक ओर जहां मुस्लिम-यादव (एमवाई) समीकरण को उनसे जोड़े हुए है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया में वो सवर्ण वोट भी उनसे छिटक गया, जो कभी मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार को राजनीतिक सबक सिखाने के लिए राजद और तेजस्वी यादव से जुड़ने की कोशिश किया था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से एक नहीं बल्कि दो-दो बार बिहार के उपमुख्यमंत्री बने, तो वो युवा जनाधार भी उनसे छिटक गया।

इस बात का खुलासा तब हुआ जब लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन का बिहार में सूबाई इंजन बने रहने के बावजूद राजद प्रमुख तेजस्वी यादव अपनी वह राजनीतिक सफलता नहीं दोहरा पाए, जैसा कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में या उससे पहले प्रदर्शित किया था। बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से महज 9 सीट ही इंडिया गठबंधन जीत सकी, जिसमें राजद को 4, कांग्रेस को तीन और भाकपा माले को दो सीटें मिलीं थीं। यह लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले राजद का बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले काफी निराशाजनक, क्योंकि तब राजद राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरा था।

वहीं, बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 में 4 सीटों में से एक भी सीट राजद या उसके इंडिया गठबंधन को नहीं मिली। जबकि पड़ोसी राज्य यूपी में इंडिया गठबंधन की सूबाई इंजन सपा ने 80 में से 43 (सपा- 37 और कांग्रेस- 6) सीटें जीतकर बीजेपी को 50 प्रतिशत से अधिक सीटों पर जबरदस्त मात दी थी और यूपी विधानसभा उपचुनाव 2024 में भी 9 में से 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। इससे तेजस्वी यादव का बिहार में चिंतित होना स्वाभाविक है। क्योंकि अब इंडिया गठबंधन की हवा निकल चुकी है और उसमें कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान तेजस्वी यादव को अपनी सियासी साख बचाने के लिए न केवल कड़ी राजनीतिक मशक्कत करनी पड़ेगी, बल्कि सियासी सूझबूझ भी नए सिरे से दिखानी होगी, जिसके आसार बहुत कम हैं।

इसलिए अब यह कहा जाने लगा है कि भाजपा के सम्राट चौधरी दांव पर तेजस्वी यादव चारो खाने चित्त हो गए हैं। जहां लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी वाले इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठजोड़ की हासिल उपलब्धि की तरह को बिहार में कुछ खास नहीं कर पाए, वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 में उससे भी बुरा सियासी प्रदर्शन किया, जिससे अब उनके नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह या जगतानंद सिंह जैसे कद्दावर नेताओं की दूसरी कतार की तरह राजद में अपने मुकाबले कोई दूसरी कतार बनने ही नहीं दिया, जिसका अब उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद जैसे भाजपा में सुशील मोदी जैसा बैकडोर शुभचिंतक रखते थे, कोई

वैसा दूसरा हमउम्र शुभचिंतक पैदा करने में भी तेजस्वी यादव सर्वथा विफल रहे हैं!

कहना न होगा कि आज तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी महज व्यक्ति नहीं, बल्कि विचार बन चुके हैं। तेजस्वी यादव जहां सेक्यूलर जमात की तरफदारी कर रहे हैं, वहीं सम्राट चौधरी अपने धर्मनिरपेक्ष मिजाज के बावजूद प्रबल हिंदुत्व के समर्थकों की एकमात्र उम्मीद बनकर उभरे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरह दबंगई पूर्वक अपनी बात रखते हैं। यही वजह है कि पहले उन्हें बीजेपी ने मंत्री बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका दिया और उसके बाद सीधे उपमुख्यमंत्री बना दिया। वहीं, सम्राट चौधरी के बढ़ते सियासी ग्राफ का सेंसेक्स इस बात का संकेत दे रहा है कि भविष्य में तीसरी पीढ़ी के भाजपा नेताओं से जब प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री या फिर देश में ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने की बात छिड़ेगी तो सम्राट चौधरी के नामों को खारिज करना इसलिए भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी भारत में वो एकमात्र ऐसे भाजपा नेता हैं जिन्हें न केवल पीएम नरेंद्र मोदी और एचएम अमित शाह पसंद करते हैं, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके सियासी अंदाज को तवज्जो देते हैं।

यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बिहारवासी यह समझ सकें कि सियासत एक चक्रब्यूह है, जिसे अमूमन तलाश किसी अभिमन्यु की रहती है, लेकिन समकालीन अर्जुन वह गलतियां नहीं दुहराता, जो महाभारत काल में दुहराई जा चुकी हैं। आज लालू प्रसाद और शकुनी चौधरी जैसे सियासी धुरंधर पग-पग पर अपने पुत्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार की राजनीति को लगभग 15 वर्षों तक (1990-2005) अपने हिसाब से हांकने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के तेजस्वी पुत्र तेजस्वी यादव हैं, जबकि उस दौर में भी लालू प्रसाद को कड़ी सियासी चुनौती देने वाले उनकी ही सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी के यशस्वी पुत्र सम्राट चौधरी हैं, जो बिहार के सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। यह उनके राजनीतिक सूझबूझ का ही तकाजा है कि आज वो कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा को काफी पीछे छोड़ चुके हैं, जो उनके पिता शकुनी चौधरी के प्रबल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी समझे जाते थे। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी जितना फूंक-फूंक कर सियासी कदम उठा रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि अपने स्वर्णिम राजनीतिक भविष्य के लिए वह कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहते हैं। वहीं, पटना से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से अपने शुभचिंतकों से जुड़े दिखाई प्रतीत होते हैं, उससे उनके प्रतिस्पर्धी नेता भी खुन्नस खा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी असरदार मौजूदगी भी दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है।

राजनीतिक लोग बता रहे हैं कि कभी नीतीश कुमार को सियासी आईना दिखाने वाले सम्राट चौधरी अब परिस्थितिवश जितना बेहतर तालमेल प्रदर्शित कर रहे हैं, उसका इशारा भी साफ है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक सूर्य अस्त होते ही सम्राट चौधरी उस सियासी शून्य को भरकर बिहार भाजपा को वह राजनीतिक ऊर्जा प्रदान करेंगे, जो उसे इन दिनों यूपी से महाराष्ट्र तक मिल रही है। ऐसा तभी संभव होगा, जब तेजस्वी यादव को बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में एक और शिकस्त मिलेगी। टीम भाजपा अभी अपने इसी मिशन में जुटी हुई है। उधर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अपनी शेखपुरा यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता देवेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर सियासी पारा हाई कर दिया है। इस मुलाकात के बाद जिले की सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने पंचायत की समस्याओं को लेकर तेजस्वी से मुलाकात की। जबकि सियासी हल्के में यह चर्चा है कि राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा अपनी लोकसभा चुनाव 2024 की हार से भाजपा से भीतर ही भीतर चिढ़े हुए हैं और अपने नेताओं को तेजस्वी यादव के पीछे लगा दिया है, ताकि समय आने पर अपने साथ हुए सियासी छल का बदला ले सकें।

आपको पता होगा कि जब-जब भाजपा नीतीश कुमार के करीब जाती है तो लाचारी वश उसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दूरी बनानी पड़ती है। वहीं, लोजपा नेता चिराग पासवान की पूछ भी घट जाती है। हालांकि, दलित नेता होने के चलते चिराग को उपेंद्र से ज्यादा तवज्जो मिलती है। नीतीश कुमार के ही चक्कर में कभी भाजपा जॉइन किये आरसीपी सिंह भी आज सियासी नेपथ्य में चले गए हैं। वहीं, बिहार की राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले नीतीश कुमार ने बिहार के अधिकांश रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए जिस तरह से अपनी सूबाई बादशाहत बनाए हुए हैं, उसे भी यदि सम्राट चौधरी निकट भविष्य में विनम्रता पूर्वक तोड़ दें तो किसी को हैरत नहीं होगी। क्योंकि भले ही वह आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं हैं, लेकिन संघ और भाजपा की एक-एक राजनीतिक कड़ी को बखुबी जोड़ते जा रहे हैं, ताकि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही बिहार में बन सके। उनके इस उद्देश्य की पूर्ति में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव का सक्रिय सहयोग भी उन्हें मिल रहा है, ऐसा पार्टी सूत्र बताते हैं।

देश में मतदान केंद्रों को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना होगा

आरके सिन्हा

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के लिए हुए चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। अब दोनों राज्यों में नई सरकारों का गठन भी हो गया है। लेकिन, प्रश्न यह उठता है कि क्या दोनों राज्यों में मतदान का प्रतिशत क्या किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं! तो फिर किया क्या जाए! पर यह तो पूरे तो पूरे देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों को यह सोचना ही होगा कि चुनावों में मतदान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, सकारात्मक पहलू यह है कि मतदान में समग्र सुधार हुआ है।

इस बदलाव का श्रेय, हालांकि अपेक्षाकृत धीमा और क्रमिक है, इसका मुख्य रूप से श्रेय भारत के वर्तमान चुनाव आयोग को जाता है। मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग इस बार काफी सक्रिय था। इसके अभियान में, सोशल मीडिया सहित, स्थानीय हस्तियों-क्रिकेटरों से लेकर फिल्म सितारों तक को भी शामिल किया गया है।

हालांकि यह मानना होगा कि देश के शहरी इलाकों में मतदान कमोबेश कम ही रहता है। शिमला से सूरत तक शहरी मतदाता की उदासीनता लगातार बनी हुई है। यह रुझान नया नहीं है। चुनावों के पहले तीन दशकों में, शहरी मतदाताओं की भागीदारी काफी बेहतर रहती थी। यह समझना होगा कि शहरी भारत, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश का लगभग सारा सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) शहरों में ही सिमटा है। जनगणना के आंकड़ों को माने तो देश की 31 फीसदी आबादी शहरों में रहती है। हालांकि गैर-सरकारी आंकड़े शहरी आबादी कहीं अधिक होने का दावा करते हैं। इन शहरों में रोजगार के अवसर हैं। सारे देश के नौजवानों के सपने इन्हीं शहरों में पहुंचकर साकार होते हैं। पर नीति निर्धारकों के फोकस से कहीं दूर बसते हैं शहर। जाहिर है, इस कारण से मतदाता निराश होने लगता है अपने जनप्रतिनिधियों से। उसे लगता है कि जब उसके नेता निकम्मे होंगे तो वह वोट क्यों करे।

मतदाताओं को नेता बार-बार निराश करते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि अगर देश में मतदान केंद्रों की तरफ फिर से मतदाताओं को बड़े पैमाने पर लाना है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की ही नहीं है। उन्हें भी जनता से सीधा संपर्क बनाकर रखना होगा। उन्हें भी जनता के मसलों को लेकर संवेदनशील बनना होगा। पहले से ही सक्रिय, चुनाव आयोग को अधिक से अधिक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, मतदान केंद्रों को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना होगा। इसमें पर्याप्त पार्किंग और आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र जैसे सुधार शामिल हो सकते हैं।

हिंदुओं की अनदेखी करने वाले नेताओं को बदलनी होगी अपनी सोच

संजय सक्सेना

बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्ध सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जलाया व मारा जा रहा है। उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं। माताओं व बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंजर ऐसा है कि किसी की भी रूह कॉप जाये। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके सामने यूपी के संभल में जो कुछ हुआ कोई मायने नहीं रखता है। हाल में बहराइच में हुई हिंसा भी बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ हो रहे अत्याचार के सामने काफी छोटी नजर आती है। क्योकि संभल हो या बहराइच की हिंसा दोनों ही को विपक्ष कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर हंगामा खड़ा कर रखा है। संभल और बहराइच पर जितना बवाल गांधी परिवार और अखिलेश यादव मचा रहे हैं उतनी ही चुप्पी वह बांग्लादेश में हिन्दुओं और दलितों के साथ हो रहे खून खराबे को लेकर साधे हुए हैं। अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा-दलित और अल्पसंख्यकों की बात जरूर की जाती है,लेकिन हकीकीत यही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक के आगे किसी को तरजीह नहीं देते हैं। अखिलेश दलितों और पिछड़ों की बात सिर्फ इस वर्ग के वोटरों को गुमराह करने के लिये करते हैं। इसी तरह से दलितों और पिछड़ों को इंसाफ दिलाने के लिये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी टीम जातिगत जनगणना कराये जाने के लिये हाय-तौबा तो करती है,लेकिन उनका भी इससे कोई लेनादेना नहीं है। उनको भी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नजर आता है।

दरअसल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जेदारी के चक्कर में एक-दूसरे के साथ-साथ (इंडिया गठबंधन में शामिल दोनों दल) होते हुए भी सियासी दुश्मन बनते जा रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की खातिर यूपी में राहुल गांधी सपा प्रमुख की कंधे पर चढ़कर उनकी पीठ में 'छुरा' भोंकने की कोशिश कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जिन्होंने भी नेताजी मुलायम सिंह के बाद मुस्लिम वोटरों को अपने जाल में फांस रखा है वह मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ कतई ढीली करने को तैयार नहीं है। इसी के चलते यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राह जुदा होती जा रही है। इसी

साल हुए लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर हाल में सम्पन्न नौ विधान सभा सीटों की, दोनों ही बार अखिलेश ने कांग्रेस के साथ होते हुए भी उससे दूरी बनाये रखी। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए कुछ सीटें कांग्रेस के लिये छोड़ भी दी थीं, लेकिन उप चुनाव में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी।

आलम यह है कि जब संभल में हुई हिंसा के बाद राहुल गांधी ने वहां जाने का कार्यक्रम बनाया तो समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश के चचा रामगोपाल यादव इसे राहुल की नौटंकी करार दे दिया। इसको लेकर कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच एक-दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई, लेकिन रामगोपाल यादव की बात सच थी। इस बात का अहसास जल्द हो भी गया। ऐसा इसलिये था क्योंकि राहुल गांधी और उनकी नई-नई सांसद बहन प्रियंका वाड्रा को जब लोकसभा में संभल के पीड़ितों की आवाज उठाने का मौका मिला तो इन दोनों (राहुल-प्रियंका) के साथ-साथ पूरी कांग्रेस अडानी-अडानी करती रह गई। कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं ने एक भी शब्द संभल हिंसा को लेकर नहीं बोला।

बांग्लादेश में हिन्दुओं और खासकर दलितों के खूब खराबे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की चुप्पी न तो बीजेपी को रास आई न ही बसपा सुप्रीमों मायावती को यह बर्दाश्त हुआ। योगी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे कुछ ज्यादा ही दुखी हैं। वह राहुल और अखिलेश जैसे नेताओं का नाम लिये बिना सवाल करते हैं आज कुछ लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। वे ही लोग समाज में झूठ फैला रहे हैं। हैदराबाद के निजाम और उनके रजाकारों की ओर से जब दलितों के गांव जलाए जा रहे थे तब भी वे चुप थें उस दौरान उनका शोषण हो रहा था। तब भी बाबा अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था कि निजाम की रियासत के सभी दलित रियासत को छोड़कर महाराष्ट्र चले जाएं, लेकिन अपना धर्म और मत न बदलें। पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक हिंदुओं की घटती आबादी पर सीएम योगी ने कहा कि साल 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की बड़ी तादाद में आबादी रहती थी। बांग्लादेश में साल 1971 तक 22 फीसदी हिंदू रहा करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 6 से 8 फीसदी ही रह गई है। योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग हमेशा दलितों को अपना वोट बैंक बना कर उनका शोषण करते आए हैं, वे आज बांग्लादेश की घटना पर मौन हैं. उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। वे सच को स्वीकार नहीं कर सकते और न ही सच बोल सकते हैं। सिर्फ संविधान की प्रति दिखाकर ढोंग कर रहे हैं। उन्हें बाबा साहेब के मूल्यों से कोई लेना-देना ही नहीं है।

ऐसे ही आरोप बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगा रही हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को लेकर विपक्षी दलों को घेरा और पूछा कि मुख्य विपक्ष दल होने के बाद भी कांग्रेस और सपा इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं ? ये दोनों दल सिर्फ मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सिर्फ संभल हिंसा की बात कर मुस्लिम समाज को लड़वा रही हैं। मायावती ने मांग की कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश के दलितों को भारत लाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि संसद चल रही है और विपक्षी दल देश और यहां के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी हुईं हैं। इन्हें बाकी मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल मुस्लिम समाज को भी तुर्क और नॉन तुर्क को आपस में लड़ा रही है, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। कई दलों के नेता तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर चुप्पी साध रहे हैं।

सीरिया में असली चुनौती अब शुरू होगी

अनिल त्रिगुणायत

सीरिया पर एचटीएस यानी हयात तहरीर अल-शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों का कब्जा और तानाशाह बशर-अल-असद का सत्ता छोड़कर भागना पश्चिम एशिया में पिछले कुछ समय से जारी उथल-पुथल में एक नया मोड़ है। इस घटनाक्रम ने दो बातों की याद दिला दी है। एक बात तो अरब विद्रोह से ही जुड़ी हुई है। वर्ष 2011 में हुए अरब विद्रोह का आखिरी केंद्र सीरिया था। तब आंदोलनकारियों ने मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया और यमन में सत्ता पलट दी थी। उस समय सीरिया के तानाशाह असद को सत्ता से बाहर करने की कोशिश का सफल होना तो दूर, उल्टे आंदोलनकारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन 2011 में शुरू हुई लड़ाई 2024 में अपने अंजाम पर पहुंची, और असद को सत्ता छोड़नी पड़ी।

दूसरी बात यह कि असद के परिवार समेत भाग जाने के बाद विद्रोहियों की भीड़ जिस तरह राजधानी दमिश्क और अलेप्पो स्थित असद के राजमहलों में घुस गयी, उसने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी निवासों में भीड़ के घुसने की याद ताजा कर दी है। विद्रोहियों ने महलों से जो तसवीरें और वीडियो शेयर किये हैं, उनसे असद की आलीशान जीवनशैली की झलक मिलती है। असद को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का निरंतर सहयोग तो मिलता ही रहा था, ईरान के अलावा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लिए भी सीरिया एक बड़ा रणनीतिक केंद्र था। लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध में अपनी पूरी ऊर्जा लगा लेने के कारण सीरिया को दी जा रही रूसी मदद में कमी आने लगी थी। असद के कमजोर पड़ने का यह एक कारण है।

हालांकि अब भी उसे रूस का समर्थन मिला हुआ है। सीरिया से भागे असद के रूस में शरण लेने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद सीरिया से तानाशाह असद का भागना रूस और ईरान के लिए बड़ा रणनीतिक झटका तो है ही। इससे रूस के लिए जहां पश्चिम एशिया में अपना मजबूत आधार खत्म हो गया है, वहीं ईरान के लिए

हिजबुल्लाह से संपर्क साधने का रास्ता बंद हो गया है। बल्कि सीरिया के इस घटनाक्रम ने ईरान के लिए नयी चुनौती खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ, सीरिया से असद की विदाई अमेरिका और तुर्की के लिए बड़ी सफलता है। हालांकि सच तो यह है कि सीरिया में असद के पांव उखड़ जाने का अंदाजा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं था। उनका आकलन था कि इस बार भी असद विद्रोहियों को तितर-बितर करने में सफल हो ही जायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पश्चिम एशिया के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो सीरिया का घटनाक्रम इस्राइल के लिए भी राहत प्रदान करने वाला है, लेकिन फर्क यह है कि इस्राइल को इससे सीधे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सीरिया में हुए बदलाव पर असंख्य लोग खुश हैं। इनमें सीरिया के नागरिक तो खैर हैं ही, जो दशकों से असद परिवार की तानाशाही झेल रहे थे। लंबे समय से जारी गृहयुद्ध के कारण लगभग 15 लाख सीरियाई देश छोड़कर लेबनान भाग गये थे। वे लोग सीरिया के घटनाक्रम से बहुत खुश हैं और अपने देश लौटना चाहते हैं।

लेकिन कायदे से देखें, तो सीरिया के लिए चुनौती अब शुरू हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया और यमन में जन आंदोलन से सत्ता परिवर्तन का कोई लाभ नहीं हुआ, उसी तरह तानाशाह असद से छुटकारा पाने के बाद सीरिया अब नयी मुश्किलों में फंस सकता है। हालांकि ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि सीरिया में असद के खिलाफ लड़ाई में जितने भी विद्रोही गुटों ने भाग लिया, कमोबेश उन सबका लक्ष्य सीरिया को असद की तानाशाही से देश को मुक्त करना था। ऐसे में, फौरी तौर पर कोई विद्रोही संगठन सीरिया पर तानाशाही थोपेगा, इसकी आशंका कम ही है। लेकिन यह भी सही है कि असद के खिलाफ जिन विभिन्न समूहों ने लड़ाई लड़ी, उन सबके बीच एकता और तालमेल बनाने का काम बहुत आसान नहीं होने वाला।

सीरिया में रहने वाले विभिन्न समुदायों, नस्ली समूहों और विभिन्न धार्मिक आस्था में यकीन रखने वाले लोगों को एकजुट करने के लिए धैर्य और दूरदृष्टि की जरूरत पड़ेगी। फिर अमेरिका से लेकर तुर्की तक ने असद के खिलाफ लड़ाई में चूंकि साथ दिया, ऐसे में, तख्तापलट के बाद नयी सत्ता में उनके भी अपने स्वार्थ हो सकते हैं। खासकर तुर्की की भूमिका इसमें बड़ी हो सकती है। हालांकि विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने कहा है कि यह घटनाक्रम इस इस्लामी देश के लिए बड़ी जीत है और सीरिया अब स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। पर असलियत में विद्रोहियों के लिए एक देश के रूप में सीरिया को एकजुट करने का काम ही बहुत मुश्किल होने वाला है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद दशकों से असद की कैद में रहे लोगों की रिहाई सबसे बड़ा काम है। तानाशाह असद ने आम नागरिकों के अलावा बड़ी संख्या में मानवाधिकारवादियों को जेलों में बंद कर रखा था। दशकों से जारी व्यवस्था को बदलने में भी, जाहिर है, समय लगने वाला है।

सीरिया में शांति और स्थिरता कायम करने के अलावा लोगों की बेहतरी के लिए भी काम करना पड़ेगा। वहां की 90 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे बतायी जाती है। दशकों के गृहयुद्ध को देखते हुए उसके पास अपने संसाधन बहुत कम बचे हैं। सीरिया दुनिया के चंद उन देशों में है, जिसके नागरिक दशकों से जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। ऐसे में, वैश्विक मदद के बगैर तो सीरिया खड़ा हो ही नहीं सकता। असद के भाग जाने के बाद पलायन कर चुके लाखों लोग सीरिया वापस लौटना चाहते हैं। उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

यूनुस से ज्यादा उम्मीदें लगाना बेमानी होगी

आनंद कुमार

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सहयोगात्मक रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कूटनीतिक संघर्षों से जुड़ी घटनाओं की वजह से तेजी से खराब हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा भारत से शरण मांगने के बाद और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों और भारत में बांग्लादेशी मिशन पर हाल ही में हुए हमले से तनाव और बढ़ गए हैं। बीते 30 नवंबर को ढाका से होकर जाने वाली अगरतला-कोलकाता बस पर बांग्लादेश में हमला हुआ, जिससे दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ गया। जवाबी कार्रवाई में, दो दिसंबर को त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेशी मिशन पर हमला किया गया, जिसके बाद ढाका ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। बांग्लादेश ने वियना संधि (1961) के उल्लंघन का हवाला देते हुए भारतीय दूत को तलब किया, जो मेजबान देशों को राजनयिक परिसर की सुरक्षा करने के लिए बाध्य करता है। हालांकि भारत ने इस घटना पर खेद जताते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया और लापरवाही के लिए तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। लेकिन स्थिति तब और बिगड़ गई, जब बांग्लादेश ने अगरतला और कोलकाता से अपने मिशन प्रमुखों को वापस बुला लिया। यह ढाका और नई दिल्ली के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। इससे पहले प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुखर समर्थक चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से स्थिति और भी खराब हो गई। दास को कथित तौर पर देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया गया था। आरोप स्पष्ट न होने के बावजूद उन्हें जमानत नहीं दी गई, जिससे पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। खबरें बताती हैं कि शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2,000 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिनमें आगजनी, लूटपाट, मंदिरों में तोड़फोड़ और देवताओं का अपमान शामिल है। भारत ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इन हमलों के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, बांग्लादेशी अधिकारियों ने शांतिपूर्ण मांग करने वाले एक धार्मिक नेता को निशाना बनाया है। नई दिल्ली ने दास के खिलाफ आरोपों की आलोचना करते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। भारत की चिंताओं को दूर करने के बजाय, ढाका ने इन मुद्दों को 'आंतरिक मामला' बताकर खारिज कर दिया। बांग्लादेशी सरकार ने भारत के बयानों को 'दोनों देशों के बीच मित्रता और समझ की भावना के विपरीत' बताया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और मौजूदा सरकार से अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठाने का आग्रह किया। इस कूटनीतिक गतिरोध ने भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश की राजनीति शुरू से विभाजित रही है। वहां की मुक्ति-विरोधी ताकतें हमेशा से ही भारत विरोधी रही हैं। सत्ता से शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ गई हैं। भारत में रह रहीं हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए उन पर 'नरसंहार' में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। बदले में यूनुस सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, जिसने दरार को और गहरा कर दिया है।

समय तेजी से करवट ले रहा है तथा लोगों के जीवन में जटिलताएं भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। परेशानी एवं जटिलता भरे इस माहौल में भी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति तथा अपने खान-पान एवं परहेज संबंधित समस्याओं को लेकर जागरूक हैं तथा इनके समाधान के लिए आतुर रहते हैं। उनकी तमाम समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं न्यूट्रीशनिस्ट।

स्वस्थ जीवन की आधारशिला रखता है

न्यूट्रीशनिस्ट

एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले नागरिक से लेकर खिलाड़ियों के लिए जरूरी फूड सप्लिमेंट तक का उपाय इन्हीं न्यूट्रीशनिस्टों के जरिए होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि न्यूट्रीशन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए फूड एवं अन्य पदार्थों को नियंत्रित करने का विज्ञान है। आज यह अपनी उपयोगिता के चलते नये प्रोफेशन का रूप अख्तियार कर चुका है। एक न्यूट्रीशनिस्ट का काम जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए खान-पान के तौर-तरीकों तथा अच्छे स्वास्थ्य के मद्देनजर जरूरी चीजों को बढ़ावा देना होता है। यह सारी क्रियाविधि मनुष्य की उम्र पर निर्भर करती है। इसके अलावा उनके रूटीन, बीमारी तथा कार्य के स्वरूप को देखते हुए खाद्य पदार्थों की रूपरेखा तय की जाती है। यह सुखद संकेत है कि न्यूट्रीशन के सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं के जरिए लोगों के अंदर व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। न्यूट्रीशनिस्ट अपने ज्ञान एवं शोधों के द्वारा खाद्य पदार्थों की सूची तैयार करता है तथा उस आधार पर उसे हॉस्पिटल, फिजिकल ट्रेनिंग कैम्प, पर्वतारोहियों आदि के लिए निर्धारित करता है। इन खाद्य पदार्थों में विटामिंस, मिनरल्स, आयरन आदि होते हैं, जो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। पाचन क्रिया के अध्ययन व शोधों से यह पता चला है कि शरीर में अधिकांश रिएक्शन एवं शारीरिक परेशानियां संतुलित आहार न लेने से होती हैं। इन बीमारियों में डायबिटीज, लीवर व पेट संबंधी समस्याएं शामिल हैं। यदि ये न्यूट्रीशनिस्ट किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग संस्थान में कार्यरत हैं तो वे अपनी प्लानिंग एवं शोधों के जरिए नए उत्पाद के सृजन की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये न्यूट्रीशनिस्ट स्वस्थ जीवन की आधारशिला रखने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

बारहवीं के बाद रखें कदम

न्यूट्रीशन के फील्ड में जो भी करियर ऑप्शन हैं, वे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बनने के बाद ही सामने आते हैं। इसके लिए लोगों को होम साइंस, न्यूट्रीशन, फूड साइंस/ टेक्नोलॉजी से सबंधित कोर्स करने अनिवार्य हैं। बैचलर कोर्स (न्यूट्रीशन एवं डायटीशियन) के लिए छात्र को विज्ञान विषयों (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, होम साइंस एवं बायोलॉजी) में पास होना अनिवार्य है। तभी बीएससी इन होम साइंस तथा अन्य बैचलर प्रोग्राम जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित अन्य विषयों को भी शामिल किया जाता है। कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो 10+2 के पश्चात चार वर्षीय फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कराते हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर न्यूट्रीशन का डायटीशियन से संबंधित कोर्स या तो दो वर्ष का है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (1 वर्षीय) के रूप में है। पीजी तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स करने के लिए फूड साइंस, होम साइंस, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बायो कैमिस्ट्री तथा मेडिसिन में बैचलर होना आवश्यक है। एमएससी इन होम साइंस भी इसी स्तर पर किया जाता है। इसके बाद पीएचडी का रास्ता खुलता है।

सिलेबस भी है कुछ खास

न्यूट्रीशन से संबंधित कोर्सों का सिलेबस काफी फैला हुआ तथा रुचिकर है। स्कूली स्तर से लेकर मास्टर एवं रिसर्च लेवल तक का पाठ्यक्रम बताता है कि स्कूलों में न्यूट्रीशन प्रोग्राम के अंतर्गत स्वस्थ खाना एवं उसके फायदे, स्वास्थ्य की जरूरत, मेन्यू डिजाइनिंग, बच्चों में फैट की मात्र, कुकिंग वर्कशॉप तथा प्रकृति के प्रति सहानुभूति दर्शाई जाती है। इसी तरह से एमएससी होम साइंस के सिलेबस में बायोकैमिस्ट्री, न्यूट्रीशन संबंधी रिसर्च, फिजियोलॉजी, बायोस्टेटिस्टिक, मनुष्य की न्यूट्रीशन की आवश्यकता, माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस के अलावा अंतिम वर्ष तक ह्यूमन न्यूट्रीशन एंड डायटेक्टिक, इंस्टीटयूशनल मैनेजमेंट एवं फूड साइंस शामिल किया जाता है, जबकि एक वर्षीय डिप्लोमा इन डायटेटिक्स एंड पब्लिक हैल्थ न्यूट्रीशन (डीडीपीएचएन) के अंतर्गत तीन माह की कंपलसरी इंटर्नशिप दी जाती है। यह इंटर्नशिप किसी हॉस्पिटल या योग्य डायटीशियन के अंडर कराई जाती है। इसमें बायोकैमिस्ट्री, न्यूट्रीशन, अप्लाइड फिडियोलॉजी, फूड माइक्रो बायोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, थिरैप्टिक न्यूट्रीशन तथा पब्लिक हैल्थ न्यूट्रीशन आते हैं।

खान-पान में अभिरुचि जरूरी

एक अच्छे न्यूट्रीशनिस्ट की रुचि खानपान एवं उसे तैयार करने में अवश्य होनी चाहिए। तभी वह इस फील्ड की बारीकियों को समझ पाएगा। समूह में अथवा व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को अपने बोलने की कला से बांधे रखने (कम्युनिकेशन स्किल्स), विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने का कौशल तथा पोस्टर, बैनर लिखने संबंधी ज्ञान भी कदम-दर-कदम काम आता है। उनकी वाणी में मिठास हो तथा मरीज के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाने की कला जानते हों। किसी भी संगठन के लिए प्लानिंग एवं इनके प्रशासनिक कार्यों को संभालने के साथ ही शारीरिक रूप से फिट तथा एक टीम लीडर की भांति काम करने का जज्बा सफलता का पैमाना तय कर सकता है। विज्ञान में अभिरुचि तथा उत्तरदायित्व जैसे गुणों को भी एक न्यूट्रीशनिस्ट के अंदर परखा जाता है।

क्या काम है न्यूट्रीशनिस्ट का

एक न्यूट्रीशनिस्ट का कार्य क्षेत्र काफी फैला हुआ है। फूड की प्लानिंग, न्यूट्रीशन प्रोग्राम तैयार करने, बीमारियों तथा जंक फूड से बचाने, पोषक गुणों से युक्त खाना खाने को प्रेरित करने से लेकर फूड सर्विस सिस्टम को प्रमुख संस्थानों जैसे स्कूल, हॉस्पिटल आदि जगहों पर प्रमोट करने संबंधी सभी कार्य इनके जिम्मे होते हैं। कुछ प्रमुख कार्य क्षेत्र इस प्रकार हैं-

क्लीनिकल डाइटीशियन- इनका कार्य किसी हॉस्पिटल, नर्सिंग केयर सेंटर अथवा अन्य संस्थानों में मरीजों को न्यूट्रीशन से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना है। वे पता लगाते हैं कि मरीज को न्यूट्रीशन की कितनी आवश्यकता है तथा उसे किस रूप में इसे दिया जा सकता है। इसके बाद मिलने वाले परिणामों तथा डॉक्टर के साथ न्यूट्रीशन संबंधित आश्यकताओं पर चर्चा करते हैं।

कम्युनिटी डाइटीशियन - इनकी प्रमुख भूमिका व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में हैल्थ को बढ़ावा देने के लिए न्यूट्रीशन प्रैक्टिस को कारगर बनाना है। इनके काम करने का स्थान मुख्यतः पब्लिक हैल्थ क्लीनिक, होम हैल्थ एजेंसी तथा हैल्थ मेंटीनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनिटी डाइटीशियन किसी भी व्यक्ति अथवा उसके परिवार की डाइट को समझने, न्यूट्रीशन केयर प्लान तैयार करते हैं।

मैनेजमेंट डाइटीशियन - ये किसी भी कंपनी, स्कूल, कैफिटेरिया अथवा बड़े पैमाने पर हैल्थ केयर से संबंधित सुविधाओं की प्लानिंग करते हैं तथा उन्हें तैयार भी करते हैं। इसके लिए वे सीधे तौर पर या कड़ी के रूप में डाइटीशियन, फूड सर्विस वर्कर को अनुबंधित करते हैं। बजट, जरूरी उपकरणों, गुलेशन आदि कार्य भी इन्हीं के जिम्मे होता है।

कंसल्टेंट डाइटीशियन - ये प्राइवेट प्रैक्टिस के जरिए लोगों को हैल्थ केयर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ये अपने क्लाइंट्स को वेट कम या अधिक करने, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने जैसे कार्यों की स्क्रीनिंग करते हैं। कुछ तो वेलनेस प्रोग्राम, स्पोर्ट्स टीम, सुपर मार्केट एवं अन्य न्यूट्रीशन से संबंधित बिजनेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

कोचिंग संस्थान - न्यूट्रीशनिस्ट के लिए कोई कोचिंग सेंटर जैसी संस्था नहीं है। इसके लिए न्यूट्रीशन कंसल्टेंट जगह-जगह वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन कर पेशे तथा इस फील्ड के प्रति जागरुकता फैलाते हैं। विदेशों में इससे संबंधित कई कोचिंग सेंटर कार्यरत हैं। छात्र अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए न्यूट्रीशन कंसल्टेंट या काउंसलर की मदद ले सकते हैं।

स्कॉलरशिप - कई प्रमुख संस्थान छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। इनमें कुछ तो कोर्स के दौरान प्रदान की जाती हैं तो कुछ पीएचडी के दौरान जेआरएफ के रूप में दी जाती हैं। नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद द्वारा हर साल 7-10 छात्रों को जेआरएफ प्रदान की जाती है। इसके अलावा अधिकांश संस्थान अपने छात्रों को स्कॉलरशिप अथवा फीस में छूट संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

वेतन - मुख्य तौर पर एक न्यूट्रीशनिस्ट का वेतन उसके कार्य एवं कार्य-क्षेत्र पर निर्भर करता है। फिर भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बतौर ट्रेनी-न्यूट्रीशनिस्ट ज्वॉइन करने पर 5,000 रु. प्रति माह तथा एक से दो साल का अनुभव होने पर 10,000-12,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। जो प्रोफेशनल फील्ड, टीचिंग एवं फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं, उन्हें आकर्षक सेलरी मिलती है, जबकि कंसल्टेंट न्यूट्रीशनिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस के जरिए पैसा व शोहरत दोनों कमा सकते हैं।

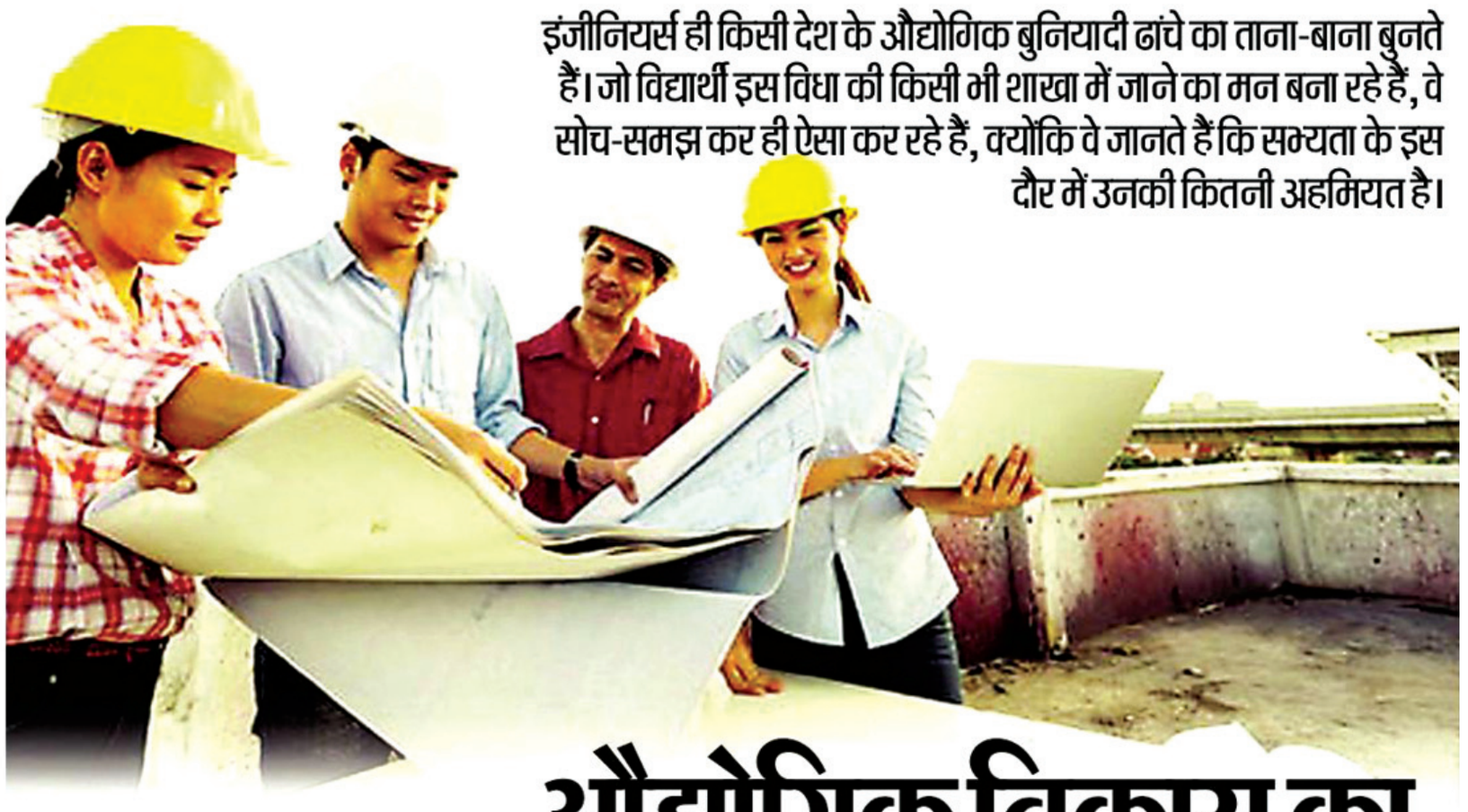

इंजीनियर्स ही किसी देश के औद्योगिक बुनियादी ढांचे का ताना-बाना बुनते हैं। जो विद्यार्थी इस विधा की किसी भी शाखा में जाने का मन बना रहे हैं, वे सोच-समझ कर ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सभ्यता के इस दौर में उनकी कितनी अहमियत है।

औद्योगिक विकास का ताना-बाना बुनते इंजीनियर्स

कुछ साल पहले तक जब करियर के इतने विकल्प नहीं थे, बच्चों को इंजीनियर बनाने का सपना मां-बाप के लिए सुनहरे कल का सपना होता था। चाहे कितनी ही परेशानी क्यों न उठानी पड़े, एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज की कक्षाओं में पहुंच गए तो तकलीफें आने वाले दिनों में बरबस मुसकराने का माध्यम बन जाती थीं। आज भी न तो इस विधा की मांग में कमी आई है और न ही इसकी प्रतिष्ठा में। इतना जरूर हुआ है कि इंजीनियरिंग की जिन शाखाओं में पहले कम विद्यार्थी जाते थे, उनमें भी करियर की वही ऊंचाई दिखने लगी है, जिसके लिए इसे जाना जाता है।

इंजीनियरिंग (अभियांत्रिकी) दरअसल किसी भी वैज्ञानिक खोज और उसके व्यावसायिक अनुप्रयोग के बीच एक कड़ी के रूप में होती है और उसी रूप में वह तमाम भावी इंजीनियरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। विज्ञान और गणित की सहायता से उपयोगी चीजों का निर्माण करने में ही इंजीनियरिंग की सार्थकता छिपी हुई है, यह किसी से नहीं छिपा है। यह एक ऐसी विशेषज्ञता प्रदान करती है, जिसके सहारे अवसरों के तमाम रास्ते खुल जाते हैं। इंजीनियर्स ही तो किसी देश की प्रौद्योगिकी व औद्योगिक बुनियादी ढांचे का ताना-बाना बुनते हैं। ये क्या नहीं करते- सड़क इनके बिना नहीं बनती, पुल नहीं बन पाते, भवनों का निर्माण नहीं होता, मशीनों का अस्तित्व नहीं होता, छोटे उपकरणों से लेकर हवाई जहाज तक तैयार नहीं होते, कार-कंप्यूटर-मोबाइल जिनके बिना इक्कीसवी सदी का आना फीका होता, इनके बिना नहीं बनते। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रगति और खुशहाली का आधार इंजीनियरिंग ही है। यही वजह है कि बारहवीं की पढ़ाई पूरी करते ही इस दिशा में बढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी बड़ी होती है। इंजीनियर किसी भी किस्म की मशीनरी, प्रोडक्ट, सिस्टम और प्रोसेस के डिजाइन व डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। किसी भी प्रोजक्ट पर कितना समय लगेगा, कितना खर्च आएगा, क्या उपकरण लगेंगे, कैसे-कैसे उसका काम आगे बढ़ेगा, इन सबके पीछे उनका ही दिमाग होता है। आज इंसान के जीवन को आसान बनाने के लिए जो कुछ भी सामने आ रहा है, वह इन इंजीनियर्स की ही मेहनत का परिणाम है। ड्राइंग टेबल पर पसरी रेखाओं में भविष्य का कौन-सा उत्पाद छिपा है, यह इंजीनियर ही बता सकता है। जाहिर है ये इंडस्ट्रियल प्लांट में काम करते हैं, प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, निर्माण स्थलों पर होते हैं, कार्यालयों में किसी अवधारणा के हर पहलू से जूझ रहे होते हैं। ये नहीं होते तो गगनचुम्बी इमारतें नहीं बनतीं, समन्दर की लहरों पर या गहराई में चलना नामुमकिन होता, आकाश में उड़ने की तो सोची ही नहीं जा सकती थी, कंप्यूटर कहां से आता, गेम कहां से बनते, बटन दबाते ही अमेरिका तो छोड़िए पास के शहर में किसी से बात नहीं हो पाती। जो विद्यार्थी इस विधा की किसी भी शाखा में जाने का मन बना रहे हैं, वे नाहक ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सभ्यता के इस दौर में उनकी कितनी अहमियत है।

नौकरी के अवसर

इंजीनियर्स के लिए अवसरों की कमी नहीं है। वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नौकरी कर सकते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों में काम कर सकते हैं, रक्षा सेवा में जा सकते हैं, निजी संस्थानों में काम कर सकते हैं, पावर प्लांट्स, अस्पतालों या बैंकों में काम कर सकते हैं या फिर अपनी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। इंजानियरिंग एक ऐसा कौशल है, जिसे जितने बड़े फलक पर आजमाया जाएगा, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। उदाहरण के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजानियर्स के लिए अधिक अवसर हैं, बनिस्पत मरीन व सेरेमिक इंजीनियर्स के। सरकार भी अलग-अलग परीक्षाओं के माध्यम से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन शाखाओं में इंजीनियर्स की भर्ती करती है।

वेतन

इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जितने अवसर मिलते हैं, वे अलग-अलग शाखाओं के हिसाब से वेतन या आमदनी का जरिया बनते हैं। सिविल इंजीनियरिंग से लेकर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तक, मरीन इंजीनियरिंग से लेकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग तक, सबकी अपनी मांग है और 10,000 रुपये प्रति माह से लेकर 30,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिल सकती है। अन्य क्षेत्रों की भांति इसमें भी अनुभव के साथ-साथ आमदनी बढ़ती जाती है। अपनी कंसलटेंसी का तो कोई वेतन जैसा गणित नहीं है, लेकिन काम जम जाने के बाद मामला लाखों-करोड़ों तक जा सकता है।

विशेषज्ञता

इंजीनियरिंग की परंपरागत दो शाखाओं- सिविल और मैकनिकल- से आगे निकलते हुए आज इसकी विभिन्न शाखाएं प्रमुखता में हैं।

एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसकी सख्त जरूरत है। कृषि से जुड़े उपकरणों के डिजाइन व निर्माण, सिंचाई व फार्म मशीनरी के लिए उपकरणों के डिजाइन व निर्माण से जुड़ी होती है यह शाखा।

एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग

आकाश मार्ग से जाना इनके बिना संभव नहीं। हवाई जहाज का डिजाइन कैसा हो कि आसानी से उड़ सके, मौसम को झेल सके, इन सब पर इसमें काम होता है। इस बात पर काफी काम होता है कि हवाई जहाज के भीतर की स्पेस कैसी हो कि ज्यादा लोग भी बैठ सकें और उड़ान में कोई दिक्कत भी न आए।

कैमिकल इंजीनियरिंग

रसायनों की दुनिया बड़ी विचित्र होती है। किसके मेल से क्या बन जाएगा, यह तो कैमिकल इंजीनियर ही बता सकता है। दवाइयां, फूड प्रोसेसिंग, पेंट, टेक्सटाइल, खाद, सौन्दर्य प्रसाधन, साबुन, तेल जैसे कार्यों से जुड़ी कंपनियों में इनकी जरूरत होती है, ताकि वे शोध से रसायनों को उपयोगी व गैर-हानिकारक बना सकें।

सिविल इंजीनियरिंग

सिविल इंजीनियरिंग की ही बदौलत ये सड़कें हैं, जिन पर तेजी से चलते हुए हम विकास कर रहे हैं, इमारतें हैं, जिनमें रहने से लेकर कार्यालयों का मामला जुड़ा है, पुल हैं, जिनके बिना नदी-नाले-पहाड़-समन्दर कुछ भी पार करना असंभव होता। और तो और अपवहन प्रणाली (ड्रेनेज सिस्टम) इनके बिना नहीं बनती और शहरों का क्या हाल होता, आज आसानी से समझा जा सकता है। हड़प्पा काल तक के लोगों ने जब इनकी अहमियत समझी तो आज तो इनके बिना एक पल नहीं रहा जा सकता।

कंप्यूटर इंजीनियरिंग

आज कंप्यूटर का जमाना है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन कंप्यूटर की सहायता से आज जो कुछ हो रहा है, वह इसके इंजीनियरों का ही तो कमाल है, जो इसके डिजाइन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर पर बड़ी बारीकी से काम करते हैं और तब जाकर कहीं एक ऐसी प्रणाली बन पाती है, जिसके सहारे काम आसान हो पाते हैं।

एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग

पर्यावरण ही तो हमारे जीवन के लिए सबकुछ है। यदि यह दूषित-प्रदूषित है तो हमारे लिए खतरा है। इससे जुड़े इंजीनियर उन परेशानियों को चिह्नित करते हैं और उनका समाधान ढूंढ़ते हैं। हवा-पानी की स्वच्छ उपस्थिति को सुनिश्चित करना, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नियंत्रित रखना, पेड़-पौधे बनाए रखना, ये सब इन्हीं का तो काम है।

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो, टीवी इत्यादि के डिजाइन, निर्माण व चलाने में इनकी भूमिका होती है। इनके बिना ऐसा नहीं हो पाएगा कि इस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर उपकरण बनाए जाएं।

मरीन इंजीनियरिंग

समन्दर की सतह पर या फिर गहराइयों में उतरने के लिए जिन जहाजों, उपकरणों व अन्य मशीनरियों की जरूरत होती है, मरीन इंजीनियर इनसे जुड़ी हर बात पर खोज करते हैं, सुधार करते हैं और संसार को खारे पानी के साथ मीठा बर्ताव करना संभव बनाते हैं।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

आज जितनी भी मशीनरियां हैं और जिनके बिना अब काम करना कठिन लगने लगता है, वे सब मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिजाइन क्षमता, निर्माण, प्रचालन व रख-रखाव संबंधी कौशल की बदौलत हैं।

माइनिंग इंजीनियरिंग

जमीन के भीतर छिपे खनिजों को बाहर निकालने के लिए जो कुछ करना पड़ता है, वह इन इंजीनियर्स की ही देन है। जमीन के नीचे सुरंग बनाने से लेकर खनिजों को बाहर निकालने तक का काम इनके सहारे चलता है।

पेट्रोलियम इंजीनियरिंग

आज पेट्रोलियम उत्पादों की जरूरत इतनी बढ़ गई है कि उनके बिना विकास का पहिया रुकने का खतरा है। तेल भंडारों की खोज करना, तेल को निकालना, रिफाइनरी तक सुरक्षित पहुंचाना इस शाखा में आता है।

जाहिर है इंजीनियरिंग की इन व अन्य तमाम शाखाओं में करियर डिजाइन की संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत है तो इस बात की सही समय पर, सही तरीके से तैयारी कर इंजीनियरिंग की परीक्षा दी जाए और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाई जाए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

प्रदर्शन के दौरान राहुल ने दिया राजनाथ को गुलाब और तिरंगा

नईदिल्ली। बुधवार को संसद के बाहर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का यह एक और दिन देखने को मिला। हालांकि, इस बार कांग्रेस सांसदों ने एनडीए सांसदों को मास्क, टी-शर्ट और बैग के बाद गुलाब के फूल और राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) भी बांटा। ऐसे ही एक आदान-प्रदान में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गुलाब सौंपते देखा गया। हालांकि, राजनाथ सीधे संसद के अंदर जाते हुए देखे गए। राहुल को उनतक जाना पड़ा। जब फूल बांटे जा रहे थे, तो विपक्षी सांसदों ने तख्तियां भी ले रखी थीं, जिन पर लिखा था-देश को मत बेचने दो। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि हमने राष्ट्रीय ध्वज बांटा है और उनसे अनुरोध किया है कि देश को बेचें नहीं बल्कि इसे आगे बढ़ाएं। दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि आजकल देश को अडानी चला रहे हैं। सबकुछ उन्हें सौंपा जा रहा है और गरीबों की आवाज दबायी जा रही है। हम देश को बेचने की इस साजिश के खिलाफ हैं।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले राहुल गांधी

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि मैंने स्पीकर के साथ बैठक की। मैंने उनसे कहा कि मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां हटा दी जानी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य है कि सदन चले और सदन में चर्चा हो। वे मेरे बारे में कुछ भी कहें, हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को बहस हो। वे अडानी पर चर्चा नहीं चाहते। अंतत: हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वे हम पर आरोप लगाते रहेंगे लेकिन सदन चलना चाहिए। कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा में सरकार पर मणिपुर के हालात को छिपाने के लिए अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में सरकार ने कांग्रेस पर सोरोस के साथ मिलीभगत करके देश को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उसे देश की आंतरिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया।

बंगाल कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्ष को परेशान करने का काम सौंपा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बंगाल कांग्रेस ने गठबंधन का नेतृत्व करने को लेकर इंडिया गुट में खींचतान के बीच दावा किया है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने सोशल मीडिया पर बनर्जी की नेतृत्व क्षमताओं पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह भाजपा के साथ मिली हुई हैं। शुभंकर सरकार ने लिखा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा व्यक्त की। कोई भी गठबंधन सहयोगी इंडिया गठबंधन का दावा कर सकता है और उसका नेतृत्व करना चाहता है। हालाँकि, ममता बनर्जी जी की कार्रवाई ने कई मौकों पर भाजपा को ऑक्सीजन प्रदान की है और जब भाजपा संकट में है तो संयुक्त विपक्षी मोर्चे को पटरी से उतार दिया है।

सिसोदिया को जमानत की शर्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत

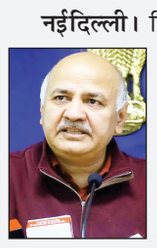

नईदिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में ढील दी है। जमानत की शर्तों के मुताबिक उनको भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना था। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह जरूरी नहीं है। वे नियमित रूप से अदालत में मामले की सुनवाई में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की जमानत की शर्तों पर छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले शीर्ष अदालत ने नौ अगस्त को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को जमानत दे दी थी।

दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी : केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने बुधवार को ऐलान किया, आप यह चुनाव दिल्ली में अपने बल पर लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। जिससे पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया। आम आदमी पार्टी यह चुनाव दिल्ली में अपने बल पर लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। सूची में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसमें 18 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो पहले पटपड़गंज का प्रतिनिधित्व करते थे, अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि शिक्षक और हाल ही में आप में शामिल हुए अवध ओझा पटपड़गंज से उनकी जगह लेंगे।

कौन बनेगा संयोजक

रार के बीच जनवरी में हो सकती है इंडिया ब्लॉक की बैठक

नईदिल्ली। लोकसभा नतीजों के बाद और हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद पहली बार संसद सत्र के बाद इंडिया ब्लॉक की बैठक होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि बैठक, जो जनवरी में होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि भाजपा से मुकाबला करने की रणनीति पर फिर से विचार करने और दिल्ली और बिहार जैसे अन्य महत्वपूर्ण राज्यों के चुनावों से पहले गति बढ़ाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन असली मुद्दा, जिस पर कुछ उग्र चर्चाएं देखने को मिल सकती हैं, वह यह हो सकता है कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा।

अब तक, तृणमूल कांग्रेस के अलावा, राजद के लालू प्रसाद यादव, एनसीपी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी को संयोजक बनाने की दावेदारी का समर्थन किया है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने यह स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सात बार की सांसद, चार बार की केंद्रीय मंत्री, तीन बार की मुख्यमंत्री और चौथे कार्यकाल के करीब हैं। इन क्रेडेंशियल्स के साथ, उसके सीवी को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि सुशासन पर उनके लगातार रिकॉर्ड और चुनावी तौर पर भाजपा को बड़े पैमाने पर हराने की क्षमता ने देश भर के कई नेताओं को उन्हें एक बड़ी भूमिका में देखने के लिए प्रेरित किया है। हालाँकि, कार्यों में बाधा कांग्रेस है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक में उनसे कहा कि चुनावी हार को बाधा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल कांग्रेस है जिसने भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई समझौता नहीं किया है और वह किसी भी नेतृत्व की भूमिका की दौड़ में नहीं है। सच तो यह है कि कांग्रेस गुट में किसी अन्य पार्टी को जगह देने की इच्छुक नहीं है। इसने नेता के रूप में राहुल गांधी की वकालत की है और इसका आधार यह है कि जब भी वह अभियान चलाते हैं तो भाजपा उन पर प्रतिक्रिया करती है।

राज्यसभा में फिर उठा सोरोस-कांग्रेस के जुड़ाव का मुद्दा

सभापति के खिलाफ नोटिस सफल नहीं होने देंगे : रिजिजू

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को भाजपा आक्रामक तेवर में दिखी। पार्टी के नेता किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वह उपराष्ट्रपति के खिलाफ एजेंडे को सफल नहीं होने देंगे। केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर सदन में अरबपति जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के कथित गठजोड़ का मुद्दा उठाते हुए सोनिया गांधी और विपक्षी दलों पर आरोप लगाए।

रिजिजू ने राज्यसभा में कहा, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। इस बीच विपक्ष के कुछ सांसदों ने कहा कि हमने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इस पर धनखड़ ने भी बीच में टोकते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि आप किसे बचा रहे हैं।

इसके बाद रिजिजू ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचकर देश की सेवा का काम किया है। इस राज्यसभा सदन के सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि उपराष्ट्रपति ने कैसे इस सदन की गरिमा को रखा है। हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग न लोकतंत्र को मानते हैं और न ही सभापति की गरिमा का ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं कि आपने बाहर टीवी पर पब्लिक के सामने उपराष्ट्रपति का नाम लेकर बेमतलब के आरोप लगाते हैं। आप इस सदन के सदस्य होने के लायक नहीं हैं। आप इस सदन के सदस्य होने का कोई अधिकार ही नहीं रखते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम सब लोग कसम खाकर आए हैं, शपथ लेकर आए हैं कि इस देश की स्वायत्ता को, एकता को रक्षा करने के लिए हम शपथ लेकर आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति की गरिमा पर अगर आप लोग हमला करेंगे तो हम बिल्कुल उनका बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इरादा है, उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस-सोरोस के कथित गठजोड़ का मुद्दा उठाते हुए कहा, आज जो सोनिया गांधी और सोरोस का लिंक सामने आ रहा है, हमने यह लिंक नहीं किया है। यह रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरी दुनिया में यह रिपोर्ट है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस के ओसीसीआरपी का जो लिंक है, यह देश के सामने है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप भारत में उसी भाषा में बात करते हैं।

हम लोग इस सदन में जितने सदस्य हैं, हमें भारत के नाम पर एक साथ एकता दिखानी चाहिए। लेकिन आप भारत विरोधियों के साथ खड़े रहते हो। आप भारत को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ खड़े रहते हो और फिर आप सभापति के खिलाफ नोटिस देते हो। ऐसा सभापति मिलना मुश्किल है। हमारे धनखड़ जी ऐसे नेता हैं, जो इस पद पर रहकर भी और इस पद के पहले भी किसान के लिए काम करते रहे हैं। हमारे देश का जो संविधान है, उसकी रक्षा के लिए उपराष्ट्रपति जी ने पहल की है। आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति पद पर आसीन हैं, हम लोग फख्र के साथ कहते हैं। चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग बात करेंगे, इस तरह नोटिस देने का काम करेंगे तो हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे।

इस बीच भाजपा ने एक्स पर कई रिपोर्ट्स के जरिए दावा किया है कि जॉर्ज सोरोस का नेहरू-गांधी परिवार से गहरा संबंध रहा है। भाजपा ने इस पोस्ट में लिखा, फोरी नेहरु, सोरोस की तरह ही हंगरी से थीं और जवाहरलाल नेहरु के भाई बीके नेहरु के साथ विवाहित थीं। यानी वह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा समय में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आंटी थीं। यह तथ्य है कि सोरोस ने फोरी नेहरु से मुलाकात की और उनसे संपर्क में रहे। उनका जुड़ाव उस समय से है, जब बीके नेहरु अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर काम कर रहे थे।

महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को हो सकता है कैबिनेट विस्तार

शिंदे के लिए गृह मंत्रालय की राह मुश्किल

मुंबई। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार 14 दिसंबर को अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है। महायुति के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, गठबंधन सहयोगियों के बीच सत्ता-बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके मुताबिक भाजपा 20 मंत्री पद अपने पास रखेगी। वहीं, शिवसेना को 12 मिलेंगी और एनसीपी को 10 से संतोष करना पड़ सकता है। 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, साथ ही शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और राकांपा प्रमुख अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब फडणवीस ने मीडियाकर्मियों से कहा था कि 16 दिसंबर को नागपुर में शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार होगा।

पोर्टफोलियो के संदर्भ में, तीनों पार्टियां यथास्थिति बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं, यानी चुनाव से पहले उनके पास मौजूद शीर्ष पोर्टफोलियो बरकरार रहेंगे, अन्य विभागों में मामूली बदलाव होंगे। जहां फड़णवीस के पास गृह मंत्रालय रहेगा, वहीं वित्त मंत्रालय एक बार फिर अजीत पवार के पास जाएगा। शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय मिलना तय है, जो उनके सीएम रहने के दौरान उनके पास था। फडणवीस बुधवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए, उनके कार्यालय ने कहा, यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली, क्योंकि वह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे।

भाजपा के एक नेता ने कहा कि शिवसेना को गृह विभाग नहीं मिलेगा और राजस्व विभाग भी आवंटित किए जाने की संभावना नहीं है। राजनेता ने कहा, बातचीत में देरी हो रही है क्योंकि तीन पार्टियां (महायुति सहयोगी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी) इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक कैबिनेट विस्तार की संभावना है। शिवसेना को गृह विभाग दिए जाने की संभावना खारिज कर दी गई है। शिवसेना को शहरी विकास तो मिल सकता है, लेकिन राजस्व मिलने की संभावना नहीं है। शिंदे के डिप्टी सीएम पद के लिए सहमत होने के बाद, सेना ने मांग की थी कि पार्टी को गृह विभाग मिलना चाहिए। हालांकि, बीजेपी ने साफ कर दिया था कि उन्हें गृह और शहरी विकास में से किसी एक को चुनना होगा।

खेल
प्रमुख समाचार

पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से हटने पर होगा भारी नुकसान

दुबई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अगर चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर चल रहे गतिरोध के कारण अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली इस 50 ओवर की प्रतियोगिता से हटने का फैसला करता है तो उसको राजस्व के भारी नुकसान के अलावा मुकदमों का भी सामना कर पड़ सकता है और वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग-थलग भी पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की प्रतियोगिताओं के आयोजन से जुड़े एक वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक ने बुधवार को बताया कि अगर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो पीसीबी के लिए टूर्नामेंट से हटने का फैसला करना आसान नहीं होगा। इस अधिकारी ने कहा, पाकिस्तान ने न केवल आईसीसी के साथ मेजबानी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी देशों की तरह उसने आईसीसी के साथ सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी से संबंधित समझौते (एमपीए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आईसीसी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एमपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई सदस्य देश आईसीसी प्रतियोगिताओं से होने वाली कमाई का हिस्सा पाने का हकदार होता है। अधिकारी में कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात किया है कि आईसीसी ने अपनी सभी प्रतियोगिताओं के लिए प्रसारक से समझौता किया है जिसमें उसने गारंटी दी है कि चैंपियंस ट्राफी सहित आईसीसी की प्रतियोगिताओं में उसके सभी सदस्य देश भाग लेंगे। आईसीसी पिछले सप्ताह चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल से करवाने पर सहमति हासिल करने में सफल रहा था। इसके अनुसार भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। इसके अलावा आईसीसी की 2027 तक होने वाली प्रतियोगिताओं में यह व्यवस्था बरकरार रहेगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 81,520 पर स्थिर निफ्टी 24,650 के करीब बंद

नईदिल्ली। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी50, बुधवार को पॉजिटिव नोट पर बंद हुए। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 81,526.14 पर बंद हुआ, जो 16.09 पॉइंट या 0.02% की बढ़त दिखाता है। आज सेंसेक्स ने 81,742.37 के हाई और 81,383.42 के लो के बीच ट्रेड किया। दूसरी ओर, एनएसई निफ्टी50 31.75 पॉइंट या 0.13% की बढ़त के साथ 24,641.80 पर बंद हुआ। निफ्टी50 का आज का हाई 24,691.75 और लो 24,583.85 रहा। निफ्टी50 के 50 स्टॉक्स में से 26 ग्रीन में बंद हुए। सबसे ज्यादा फायदा ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, ब्रिटेनिया, श्रीराम फाइनेंस, और हीरो मोटरकार्प को हुआ, जिनमें 2.50% तक की तेजी देखी गई। वहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडाणी पोर्ट, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक्सिस बैंक के 23 स्टॉक्स रेड में बंद हुए, जिनमें 1.48% तक की गिरावट दर्ज हुई।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संभाला पदभार

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की जगह संजय मल्होत्रा ने ली है। संजय मल्होत्रा ने पद संभालने के पहले कहा कि वो नए पद को समझने के बाद सबसे पहले अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सभी बेहतर कदम उठाएंगे। संजय मल्होत्रा ने नई दिल्ली में कहा कि हमें क्षेत्र, सभी दृष्टिकोणों को समझना होगा। सबसे जरुरी है कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा काम करना होगा। राजस्थान कैडर के 1990 बैट के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी मल्होत्रा ने बुधवार को ही केंद्रीय बैंक के प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाला है। बता दें कि मौजूदा आरबीआई गवर्नर पर जीडीपी वृद्धि को सहारा देने के लिए दरों में कटौती करने का भारी दबाव होने वाला है।

मारुति सुजुकी का सर्विस टचप्वाइंट को लेकर मेगा प्लान

नईदिल्ली। कार बाजार में लीडर मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा कि वह 2030-31 तक अपना कुल सर्विस नेटवर्क बढ़ाकर 8,000 टचप्वाइंट तक ले जाने की योजना बना रही है। कंपनी ने NEXA के लिए 500वां सर्विस टचप्वाइंट खोलने के साथ बताया कि फिलहाल NEXA और ARENA (मास मार्केट रिटेल चैन) के तहत उसके 5,240 टचप्वाइंट हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ ने कहा, ''हमारा उद्देश्य अपने ग्राहकों को लगातार सुविधा और बेहतर कार स्वामित्व अनुभव प्रदान करना है। इसका एक तरीका यह है कि हम अपने ग्राहकों के करीब पहुंचें, ताकि उन्हें उनके निकट ही मारुति सुजुकी सर्विस 'टचप्वाइंट' मिलने का आश्वासन मिले।'' मारुति सुजुकी ने अपने सर्विस नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बनाई है। कंपनी के मुताबिक, आने वाले समय में प्रोडक्शन और सेल्स को बढ़ाने के साथ ही सर्विस नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।

निसुस फाइनेंस सर्विसेज के आईपीओ की धमाकेदार एंट्री

नईदिल्ली। निसुस फाइनेंस सर्विसेज के शेयरों ने 11 दिसंबर को स्टॉक मार्केट में शानदार एंट्री की है। आईपीओ के तहत यह शेयर 180 रुपये के भाव पर जारी हुए थे, लेकिन मार्केट में 225 रुपये पर लिस्ट हुए, जिससे आईपीओ निवेशकों को सीधे 25% का लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग के बाद शेयर और बढ़े और 236.25 रुपये के अपर सर्किट पर पहुंच गए। इसका मतलब है कि अब आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशक 31.25% का फायदा कमा रहे हैं। निसुस फाइनेंस सर्विसेज का रू. 114.24 करोड़ का आईपीओ 4-6 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस दौरान आईपीओ को मिला-जुला रिस्पांस मिला, क्योंकि एंप्लॉयीज के लिए आरक्षित हिस्सा पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ। हालांकि, ओवरऑल यह 192.29 गुना सब्सक्राइब हुआ।

ब्याज दरों में अब कमी होनी ही चाहिए

प्रह्लाद सबनानी

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम मुद्रा नीति वक्तव्य (मोनेटरी पॉलिसी स्टेट्मेंट) दिनांक 06 दिसम्बर 2024 को प्रात: 10 बजे जारी किया है। इस मुद्रा नीति वक्तव्य में रेपो दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए इसे पिछले 22 माह से (अर्थात 11 मुद्रा नीति वक्तव्यों से) 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। यह संभवत: भारतीय रिजर्व बैंक के इतिहास में सबसे अधिक समय तक स्थिर रहने वाली रेपो दर है। इस बढ़ी हुई रेपो दर का भारत के आर्थिक विकास पर अब विपरीत प्रभाव होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर घटकर 5.4 प्रतिशत तक नीचे आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक दो माह के अंतराल पर मुद्रा नीति वक्तव्य जारी किया जाता है, परंतु पिछले 11 मुद्रा नीति वक्तव्यों में रेपो दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जबकि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर कुछ समय तक तो लगातार 6 प्रतिशत के सहनीय स्तर से नीचे बनी रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित औसत मुद्रा स्फीति के अनुमान को 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है। इसका आश्य यह है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति की दर संभवत: वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय तिमाही में भी अधिक बनी रह सकती है। इसके पीछे खाद्य पदार्थों (विशेष रूप से फल एवं सब्जियों) की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि, एक मुख्य

कारण जिम्मेदार हो सकता है। परंतु, क्या ब्याज दरों में वृद्धि कर खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति की दर को आंकने में खाद्य पदार्थों का भार लगभग 40 प्रतिशत है। यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति में से खाद्य पदार्थों के भार को अलग कर दिया जाय तो यह आंकलन बनता है कि कोर पदार्थों की मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में बनी हुई है।

खाद्य पदार्थों की कीमतों को बाजार में फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति बढ़ाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है, न कि ब्याज दरों में वृद्धि कर। इस वर्ष मानसून का पूरे देश में विस्तार ठीक तरह से नहीं रहा है, कुछ क्षेत्रों में बारिश की मात्रा अत्यधिक रही है एवं कुछ क्षेत्रों बारिश की मात्रा बहुत कम रही है, जिसका प्रभाव खाद्य पदार्थों की उत्पादकता पर भी विपरीत रूप से पड़ा है, जिससे अंतत: खाद्य पदार्थों की कीमतों में उच्छाल देखा गया है।

बाद के समय में, अच्छे मानसून के पश्चात भारत में आने वाली रबी मौसम की फसल बहुत अच्छी मात्रा में आने की सम्भावना है क्योंकि न केवल फसल के कुल रकबे में वृद्धि दर्ज हुई है बल्कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता के चलते फसल की उत्पादकता में भी वृद्धि होने की पर्याप्त सम्भावना है। इन कारकों के चलते आगे आने वाले समय में खाद्य पदार्थों की एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति की दर निश्चित ही नियंत्रण के रहने की सम्भावना है। इससे, निश्चित ही रेपो दर को कम करने की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही, अमेरिका सहित यूरोप के विभिन्न देशों में भी ब्याज दरों को लगातार कम करने का चक्र प्रारम्भ हो चुका है, जिसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा।

दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि दर के अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। क्योंकि, यह वृद्धि दर द्वितीय तिमाही में घटकर 5.4 प्रतिशत की रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के कम रहने के कई विशेष कारण रहे हैं।

क्रमश: ...

जिला भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत तैयारी हेतु बैठक आहूत

छत्तीसगढ़ सरकार मनाएगी जनादेश परब

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा सरकार बनने का एक वर्ष पूर्ण हो चुका है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 दिसम्बर 2023 को प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था जिसको भाजपा एक पर्व के रूप में मन रही है और इसे जनादेश परब का नाम दिया गया है सरकार की सालगिरह की तैयारियां जोरों पर है।

प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को बैठक के विषय में संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के एक वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 3 दिसम्बर को प्रदेश में हमारी सरकार बनी और 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण की सालगिरह है जिसे हम जनादेश परब चूंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की सरकार को उतार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः छत्तीसगढ़ की जनता अपना जनादेश दिया और प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए विष्णुदेव

सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इंगित भी किए थे , किसानों के लिए बोनस और 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी , महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है , गरीब के सर पर छत देने का वादा तात्कालिक प्रभाव से लिया गया जिसके तहत 16 लाख प्रधानमंत्री आवास की प्रक्रिया सरकार बनने के त्वरित पश्चात शुरू कर दी गई थी और ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन भाजपा सरकार ने सफलता पूर्वक किया और इसी तारतम्य में जनता को धन्यवाद देने हेतु जनादेश परब मनाया जा रहा है।

जिसमें मुख्यअतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति रहेगी ऐसे में रायपुर शहर जिला के सभी पदाधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी है जिस संदर्भ में आज की आवश्यक बैठक आहूत की गई है मुख्य रूप से मंडल क्षेत्रों से जनता को लाने ले जाने वाहन की व्यवस्था , शहर की सजावट व्यवस्था जिसके तहत स्वागत द्वार राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत होर्डिंग और भाजपा के झंडे लगाना जैसे सभी कार्यक्रम को हमे सुगमता से संपन्न करना है पहले भी रायपुर शहर जिला ने बड़े बड़े कार्यक्रमों और आमसभा को सफलता पूर्वक संपन्न किया है और इस बार भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत और आमसभा को ऐतिहासिक सफल बनाने में आप सभी अपना शतप्रतिशत प्रदान करेंगे।

संगठन शिल्पी कहे जाने वाले प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में सरकार बनने की सालगिरह के कार्यक्रम में अतिथि के रूप के सम्मिलित होने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पहुंचने वाले हैं जहां वे एक विशाल जनसमुदाय को आमसभा के रूप में संबोधित करेंगे हम सभी आज यहां इसी संदर्भ में एकत्रित हुए हैं जनादेश परब अर्थात जनादेश का त्यौहार हम सभी को धूमधाम से मनाना है इस कार्यक्रम का मुख्य भाव पूरे प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा , ग्राम मंडल क्षेत्र की जनता तक पहुंच सके और जिससे हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता बीच पहुंचा सकेंगे आप सभी संगठन पर्व संगठन चुनाव में लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता के माध्यम से ही आपकी असली मेहनत दिखाई देगी हम आशान्वित हैं कि आपके परिश्रम से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक सफल होगा ।

बाबू भैया की कलम से ✍

धान खरीदी किसानों का वार्षिक उत्सव, विपक्ष मनाती है आरोपोत्सव

धान खरीदी प्रदेश का आज के दिन सबसे बडा काम हो चुका है। इससे बड़ी व्यापक योजना दूसरी नहीं है। किसान हित की यह योजना जब से बनी है तब से ही इस पर विपक्ष हमेशा विवाद खड़ा करता ही है। चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो या भाजपा। पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में बने खरीदी केंद्रों में कितना भी सतर्कता से काम होता हो,पर विपक्ष बाल की खाल निकाल ही लेता है। फिर शुरू होता है खामियां गिनाने का दौर। सरकार किसी की भी हो आरोप से नहीं बच पाई। कम खरीदी,तौल में गड़बड़ी,बारदाना की कमी,टोकन आबंटन में गड़बड़ी,भुगतान में विलंब,मिलरों द्वारा धान का उठाव ना करना ये कामन आरोप हैं जो तत्कालीन विपक्ष के हाथ लग ही जाते हैं। प्रदेश भर में हजारों केंद्रों में खरीद में चाहे कितनी भी सतर्कता बरती जाए कुछ ना कुछ कमी तो बड़े काम में मिल ही जाती है। ना हुआ तो बारदाना की कमी ,मिलों के असहयोग से केंद्र सरकार द्वारा आबंटन के बाद भी नहीं मिल पाती,यह कमी तो मिल ही जाती है। सिस्टम में सेट कर्मचारी-अधिकारी की अपनी मानसिकता भी होती है जिसके चलते कम तौल की गड़बड़ी कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। टोकन आबंटन भी एक बड़ा व सरदर्दी का सबब बन जाता है,जब पर्दे के पीछे से कुछ विशेष निर्देश दिए जाते हैं। सरकार के बजट की भी अपनी एक मर्यादा है। उसके चलते भी अनेक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर इतने बड़े काम में कुछ ना कुछ खामियां तो मिल ही जाती हैं जो विपक्ष के लिए राजनैतिक संजीवनी का विषय बन जाता है। धरना प्रदर्शन ,आंदोलन का हाथ थाम विपक्ष जनता के बीच यह स्थापित करने का भरपूर प्रयास करता है कि ,सरकार धान खरीदी में अनियमितता कर रही है। उसको इस विरोध में अपनी विचार धारा से जुड़े किसानों का साथ भी मिल ही जाता है। चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो या भाजपा धान पर प्रतिवर्ष रार - तकरार का दौर शुरू हो जाता है। धान खरीदी की कभी विपक्ष प्रसंशा नहीं करता,कभी भी बोनस देने पर तारीफ नहीं होती,कमी ही बताई जाती है। ना वर्तमान सरकार के 3100 में धान खरीदी व 72 घंटे में भुगतान की तारीफ होती। बल्कि कोई कहीं एक दो भुगतान के विलंब की घटना अगर हो जाए तो इतना बड़ा तूफान जरूर खड़ा कर दिया जाता है,मानों सरकार कहीं भी भुगतान नहीं कर पा रही है। कांग्रेस सरकार के दौर में भी और भाजपा सरकारों के दौरान भी यही होता आ रहा है। अब तो यह लगने लगा है कि अगर धान खरीदी पर जिस सरकार के विरुद्ध कोई आरोप विपक्ष नहीं लगा पाएगी, उस सरकार का 15 साल कोई बाल भी बांका नहीं कर पायेगा। धान प्रदेश में राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। हर साल विपक्ष सरकार के खिलाफ वार करने को अपनी आरोपों की तलवार पर धार लगाता है। वो मानता है कि पांच साल अगर सफलता के साथ धान खरीदी पर एन-केन-प्रकारेण सरकार पर प्रश्नचिन्ह लगा कर बदनाम किया जाए और उसमें अगर सफल हुए तो अगली सरकार अपनी बन जाएगी। प्रदेश की 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है। राजनैतिक दलों के लिए वोट का सबसे बड़ा बैंक किसान है,उसे कौन अपने पक्ष में नहीं करना चाहेगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो किया ही जाएगा। चाहे सच बोलकर, चाहे झूठ बोलना पड़े सरकार को बदनाम करना तात्कालिक विपक्ष का सबसे बाद धर्म बन जाता है। विपक्ष ये देखना नहीं चाहता की कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए क्या किया ना यह देखना चाहता की भाजपा सरकारों ने किसानों के लिए क्या अच्छा किया। सिर्फ बाल की खाल निकाल कर उसे सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाने का काम ही विपक्ष करता है। धान खरीदी प्रदेश के किसानों के हृदय के पास है। या यूँ कह सकते हैं की किसानों की जीवनरेखा है। इस जीवनरेखा को मिटाने की कोशिश की जगह दोनों दल या कहें सभी दल मिलजुल कर किसानों का हित पर सोचें,प्रदेश में ऐसा माहौल बन सके इसका प्रयास करें तो किसानों का भला होगा। जो नहीं हो सकता उसे साफ कहें,बड़ी बड़ी बात करके अप्रत्यक्ष रूप से योजना में पलीता लगाने की सोच को छोड़ दें। पारदर्शिता का प्रयोग करें, विपक्ष की बात को नकारे नहीं सकारात्मकता से लें, अगर गलती है तो उसे स्वीकार करते हुए सुधार किया जाये। सब जानते हैं कि बड़े काम में त्रुटियां होंगीं ही और जहां इस काम में हजारों दिमाग लगे हों इसका क्षेत्र व्यापक हो तो वहां 'मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना' की स्थिति भी बन सकती है। बड़े काम में गलतियों के साथ सुधार की पूरी गुंजाइश होती ही है। सरकार सुधार करे विपक्ष उन गलतियों व सिस्टम की मनमानी को सरकार के सामने लाये, यह होना चाहिए,यही होता भी है,पर नकारात्मकता के साथ होता है। सकारात्मकता के साथ होना चाहिए। उसके बाद भी सरकार ना सुने तब आंदोलन होना चाहिए।

भारतीय भाषा दिवस पर आयोजित हुआ साहित्यिक कार्यक्रम, प्रदेश के भाषाविद् और बुद्धिजीवी रहे मौजूद

जो लोगों को जोड़े वह भाषा, भाषा से ही संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है : डॉ. सक्सेना

रायपुर। भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में किया गया। इस अवसर पर भारतीय भाषा और राष्ट्रीय एकता विषय पर मुख्य वक्ता डॉ. पूर्णेंदु सक्सेना ने कहा कि भाषा आदमी को आदमी से जोड़ने के लिए होती है, वह गोंद की तरह है लेकिन आज कुछ ताकतें भाषा के माध्यम से समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। हमारी भाषा का महत्व उसके व्याकरण नियमों में नहीं है, उनसे व्यक्त होने वाले भाव हैं।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल भी मंच पर उपस्थित थे। विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। मुख्य वक्ता ने आगे कहा कि इसको जब कठोरता में बांधने का प्रयास करते हैं, इसका वर्गीकरण कर दिया गया है। तमिल भाषा के कवियों का संगम हुआ उसमें पहले संगम के अध्यक्ष ऋषि अगस्त्य थे। अगस्त्य का केंद्र मध्य भारत था, उन्होंने दक्षिण में जाकर तमिल कवियों के संगम की अध्यक्षता की। इसका अर्थ उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में भाषा का कोई भेद नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि प्राचीन काल में भारत से कई खेप में लोग अलग अलग क्षेत्र में गए, वहां स्थानीय स्तर पर संपर्क भाषा बनती गई। लेकिन यूरोप के लोग जब अलग अलग क्षेत्रों में गए तो उन्होंने अपनी भाषा को वहां पर थोपने का प्रयास किया। भारत में विदेशियों ने भाषा का वर्गीकरण कर उन्हें विदेशी बता दिया, क्या भारत में रहने वालों की आपस में कोई भाषा या बोली नहीं थी? इस प्रकार भारत की भाषा के माध्यम से क्षेत्रों में विभाजन करने का प्रयास किया। तमिल भाषा को उत्तर से अलग करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। भारत में संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की मूल है, उनसे अलग अलग भाषा बनती गई। आज चाहे गोंडी बोली हो या तमिल उनमें संस्कृत के धातु शब्द मिलते हैं। वैदिक ज्ञान का जब बंगाल और तमिलनाडु में अध्ययन किया गया तो दोनों ही स्थान में वैदिक ज्ञान एक ही निकला। इसका मतलब है कि संस्कृत में व्यक्त ज्ञान को संरक्षित रखने का सबसे वैज्ञानिक माध्यम है। भाषा ज्ञान

और परंपरा को संरक्षित का माध्यम भी है।

मुख्य अतिथि डॉ. रमन सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा, भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, वह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आजादी के आंदोलन में भाषा कोई बाधा नहीं बनी, पूरा देश एक उद्देश्य को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा।छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करने के बाद छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद विधानसभा और न्यायपालिका में छत्तीसगढ़ी का प्रयोग किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है। भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर भाषाओं के बीच दूरी को समाप्त कर एकात्म का भाव जगाने का प्रण करना होगा। छत्तीसगढ़ में पूरे देश के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। प्रदेश में भी गोंडी, हल्बी, भतरी जैसी भाषाएं भी प्रदेश में व्यापक स्तर पर बोली जा रही हैं। सभी भाषाओं को मजबूत करने ही भारत मजबूत बनेगा।

कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए सरस्वती शिक्षण संस्थान के सचिव विवेक सक्सेना ने कहा, भारत की सभी भाषाओं में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से तमिल भाषा के महान कवि सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन, 11 दिसंबर के दिन को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि भाषा संस्कृति से जुड़ी है, अगर भाषा पुष्ट होगी तो भारतीय संस्कृति का भी विकास और प्रसार होगा। व्याख्यान के बाद विभिन्न भाषाओं में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सभी नगरी निकाय एवं पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट जाये

रायपुर। कांग्रेस के जिला एवं शहर अध्यक्षों की बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में लिया। बैठक में आसन्न नगरी निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा किया गया एवं धान खरीदी में फैली अव्यवस्था तथा इस हेतु आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस द्वारा चलाये जा रहे संविधान रक्षक कार्यक्रम एवं पिछले माह दिये गये कार्यक्रमों तथा मासिक बैठक की भी समीक्षा किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने शीघ्र ही सभी निकायों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के निर्देश दिया। उन्होंने जिला अध्यक्षों से कहा कि अपने क्षेत्र के नगर पंचायतो एवं पालिकाओं में पर्यवेक्षको जिलों से नियुक्तियां कर दे, निगमों के लिये प्रदेश में शीघ्र प्रभारी नियुक्ति किया जायेगा। उन्होंने बूथ सेक्टर, जोन एवं ब्लाक में खाली पदों पर शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिया। बैठक में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्री दीपक मिश्रा, जिलाध्यक्षगण रायपुर शहर गिरीश दुबे, रायपुर ग्रामीण उधोराम वर्मा, बलौदाबाजार हितेन्द्र ठाकुर, गरियाबंद भावसिंह साहू, धमतरी शरद लोहाना उपस्थित थे।

मानक बारदाना, नेता प्रतिपक्ष महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजनान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान उपार्जन के लिये श्री गौरी शंकर जुट मिल पश्चिम बंगाल से क्रय किये गये बरदाने को अमानक बताते हुए कहा कि, धान खरीदी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। दिनांक 05 दिसंबर 2024 को मैंने जिला बलौदाबाजार-भाटापार के धान खरीदी केंद्र तरेंगा का निरीक्षण किया था। इस धान खरीदी केंद्र पर जो जूट का नया बारदाना उपयोग में लाया जा रहा था उनमें से अनेक का वजन करवाने पर यह पाया गया की प्रत्येक बारदाने का अधिकतम वजन 480 ग्राम था। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नए जुट बारदानों का औसत न्यूनतम वजन 580 ग्राम होना चाहिए इस वजन में विचलन + 8 प्रतिशत एवं - 6 प्रतिशत मान्य है अर्थात 626 ग्राम से अधिक वजन वाले तथा 545 ग्राम से कम वजन वाले बारदाने अमानक माने जाएंगे और अमानक बारदानों का उपयोग धान अथवा चावल के लिए नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि. धान खरीदी केंद्र तरेंगा में जिन बारदानों का वजन कम पाया गया है वे सभी श्री गौरीशंकर जूट मिल पश्चिम बंगाल द्वारा निर्मित किये गये थे.

मधेश्वर पहाड़ को मिला प्राकृतिक शिवलिंग होने का गौरव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। रिकॉर्ड बुक में 'लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग' के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे प्रदेश के पर्यटन की उपलब्धियों में एक नया आयाम बताया। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि श्रीमती हेमल शर्मा और श्री अमित सोनी ने मुख्यमंत्री श्री साय से आज मंत्रालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें वर्ल्ड रिकार्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।

लंबित पेंशन प्रकरणों पर कमिश्नर नाराज

रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में लंबित पेंशन प्रकरणों पर आज विभागीय अधिकारियों और आहरण संवितरण अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पिछली समीक्षा बैठक के निर्देशों अनुसार लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की और अगले महीनें तक प्रगति दिखाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। संभागायुक्त ने आज की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। कावरे ने जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, आबकारी, राज्य कर, सामाज कल्याण, कृषि आदि विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों पर कार्रवाई की गहन समीक्षा की। उन्होंने शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों को उनकी सेवा निवृत्ति से छह महीने पहले तैयार कर कोष लेखा पेंशन कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए.

जर्मन के लोग संस्कृत को अपना रहे हैं: बैस

रायपुर। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस दूधाधारी मठ संस्कृत पाठशाला द्वारा आयोजित गीता महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए, अध्यक्षता डॉक्टर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज ने की। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता की पूजा अर्चना की कार्यक्रम अध्यक्ष एवं मठ ट्रस्ट कमेटी के सदस्यों के द्वारा पूर्व महामहिम जी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अभ्यागत ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि -सनातन धर्म में चार वर्ण बताये गये हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इन चारों के कार्यों में परिवर्तन आया है। जर्मनी में लोग संस्कृत को अपना रहे हैं लेकिन भारत में यह विलुप्त के कगार पर है। बी आर चोपड़ा और रामानंद सागर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने रामायण और महाभारत को टीवी सीरियल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। भागवत को कहने और सुनने से ज्यादा आवश्यकता है उसको आत्मसात् करना चाहिए। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर उन्होंने चिंता व्यक्त कीय

अहिल्याबाई होल्कर की त्रिशताब्दी जयंती समारोह में शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय ने दिखाई अपनी प्रतिभा

शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर में आज पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीएड और एम.एड के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

मुख्य अतिथि के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति माननीय श्री बलदेव भाई शर्मा जी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में अहिल्याबाई होल्कर के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक आदर्श शासक होने के साथ-साथ एक महान समाज सुधारक भी थीं।

मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांत

संघचालक टोपलाल वर्मा ने अहिल्याबाई होल्कर के जीवन पर एक विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे अहिल्याबाई होल्कर ने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने राज्य को समृद्ध बनाया और लोगों के जीवन में सुधार लाया। उन्होंने अपने भाषण में अहिल्याबाई होल्कर के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य, श्री आलोक शर्मा ने महाविद्यालय के मुख्य ध्येय और प्रेरक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने महाविद्यालय के संक्षिप्त इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे यह महाविद्यालय शिक्षकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कार्यक्रम का संचालन डॉ डी के बोदले ने किया। उन्होंने अपनी कुशलता से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। छात्र-छात्राओं ने अहिल्याबाई होल्कर के जीवन पर आधारित निबंध, चित्रकला और रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। इनमें से कुछ प्रस्तुतियां बेहद प्रभावशाली थीं। डॉ कल्पना देशमुख के मार्गदर्शन में

निबंध, चित्रकला और रिसर्च पेपर लेखन प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।यह आयोजन लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के जीवन और कार्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक प्रयास था। साथ ही, इस आयोजन ने छात्र-छात्राओं को उनके जीवन और कार्यों से प्रेरित होने का एक अवसर प्रदान किया।

कृषि के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने हेतु डिजीटलीकरण आवश्यक

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में आज कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली का ''उच्च, सतत और समावेशी विकास के लिए कृषि का डिजीटलीकरण'' विषय पर तीन दिवसीय 32वां वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन में देश भर के प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री, नीति निर्माता एवं शोधकर्ता शामिल हुए।

सम्मेलन में भारत में आगामी दो दशकों में कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार मंथन किया गया और घटते संसाधनों तथा बढ़ती हुई उत्पादन मांगों के युग में कृषि में डिजीटलीकरण को बढ़ावा देने तथा नवाचार एवं तकनीकी आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक देश को अपनी बढ़ती जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व दबावों को सामना करना पड़ेगा। जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों तथा जैव विविधता पर बढ़ते दबाव और उत्पादन मांगों के तेजी से बढ़ने के पूर्वानुमान के साथ कृषि क्षेत्र को इस अंतर को स्थायी रूप से पाटने के लिए परिवर्तनकारी रणनीति अपनाना होगा। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल थे तथा अध्यक्षता कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ के अध्यक्ष डॉ. पी.के. जोशी ने की। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. गिरीश चंदेल ने आने वाले समय में संसाधनों की घटती उपलब्धता, बढ़ती जनसंख्या के दबाव तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि के क्षेत्र में डिजीटलीकरण को बढ़ावा देने तथा नवाचारी प्रयास किये जाने की आवश्यकता जताई। डॉ. चंदेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में इस तरह के महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन यहां के शिक्षकों, वैज्ञानिकों तथा विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.